₹ 10

www.kewalsachtimes.com

नवम्बर 2024

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PS.-78

"मेरा पानी उतरता देख,
मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना,
मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा"

फडणवीस चलायेंगे

महाराष्ट्र सरकार

जन-जन की आवाज है केवल सच

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में रोजगार का सुनहरा अवसर

केवल सच सामाजिक संस्थान और श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट अपने भविष्य के आगामी योजनाओं में सामाजिक एवं बौद्धिक सुधार के क्षेत्र में पुर्नजागरण के शंखनाद हेतु बिहार और झारखण्ड राज्य के मेधावी/सक्षम/योग्य/दक्ष एवं कर्मठ नवयुवकों को अपने टीम में वैतनिक/अवैतनिक रूप से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करना चाहती है। उक्त स्वयंसेवी संस्थान मुख्य रूप से 'अपना घर' (वृद्धाश्रम आवास योजना), परिवार परामर्श केन्द्र, शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम (मूल रूप से निर्धन/बेसहारा लड़कियों हेतु) और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहती है। इन कार्यक्रमों से जुड़कर नवयुवक सामाजिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। उक्त संगठन इसके लिए टीम वर्क के तहत कार्य करना चाहती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समन्वयक के अधीन वार्ड/ पंचायत/ प्रखण्ड/ अनुमण्डल/जिला समन्वयकों की नियुक्ति भी करना चाहती है। इस संस्थान से जुड़कर इच्छुक नवयुवक उक्त पदों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

संस्थान

shruti कम्युनिकेशन ट्रस्ट

श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत संचालित

निबंधन संख्या : 22333/2008, आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2549-52 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1073

www.shruticommunicationtrust.org

केवल सच सामाजिक संस्थान

भारतीय सोसायटी एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधित

निबंधन संख्या : 1141 (2009-10), आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

www.ks3.org.in

Regd. Office:- East Ashok Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar)
Jharkhand State Office:- **Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi**
Mob.- 9431073769

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
COLOUR	Cover Page	3,00,000/-	N/A
	Back Page	1,00,000/-	65,000/-
	Back Inside	90,000/-	50,000/-
	Back Inner	80,000/-	50,000/-
	Middle	1,40,000/-	N/A
	Front Inside	90,000/-	50,000/-
	Front Inner	80,000/-	50,000/-

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
B & W	Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

एनडीए या इंडिया लेगा झारखंड

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद मोदी का लहर का असर पर प्रभाव पड़ा है और सिर्फ नरेन्द्र मोदी के नाम पर ही सत्ता हासिल हो जायेगा की सोच पर पश्चिम बंगाल और बिहार-झारखंड में वोटर ग्रहण लगा देती है। भाजपा ने 2014 के बाद से विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का नाम पर चुनाव नहीं लड़ता जिसका खामियाजा भी कई राज्यों के चुनाव में भुगतना पड़ा है। बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन ने पटखनी दे दी और 2024 के झारखंड विधानसभा में भी इंडिया गठबंधन ने एनडीए यानि भाजपा को परास्त कर दिया क्योंकि झारखंड में भाजपा में मुख्यमंत्री के कई उम्मीदवार थे लेकिन किसी को भाजपा ने चेहरा नहीं बनाया और हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री का खुल्लेआम चेहरा था और मईयां योजना ने चुनाव के पहले ही जीत सुनिश्चित कर दी थी। झारखंड में आदिवासियों ने हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद एकजुट होकर वोटर गोलबंद हो गये और एनडीए को पता भी नहीं चला जबकि NDA में शामिल JDU के सरयू राय सिर्फ अपनी ही सीट बचा पाने में सफल हो सकते हैं और सुदेश महतो का आजसू सिर्फ सोसल मीडिया पर ही हावि दिखता है। झारखंड में विकास के बजाय कोयले की चोरी ही प्राथमिकता बन जाता है। अब देखना है कि झारखंड किसका होगा 5 साल के लिए

24 वर्ष पहले झारखंड प्रदेश बिहार से अलग होकर अपने अस्तित्व में आया था जिसके लिए लालू यादव ने कहा था कि मेरे लाश पर बटवारा होगा लेकिन राजनीति क्या चीज है इसी बात से ही सहजता के साथ समझा जा सकता है कि झामुमो के साथ राजद मिलकर झारखंड में 2019 से सत्ता मे शामिल है। 2014 में पहली बार भाजपा ने गैर आदिवासी रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाकर झारखंड में सरकार तो चलाई लेकिन 2019 में आदिवासियों ने अपनी शक्ति का एहसास कराकर मोदी लहर के बाद भी 2019 में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया तो 2024 में भी लगातार दूसरा शतक लगाकर हेमंत सोरेन अपनी शक्ति का एहसास करायेंगे यह होता दिख रहा है। चुनावी शंखनाद के बीच हेमंत सोरेन की ED की कूटनीति ने जहां INDIA गठबंधन को एकजुट रहने पर विवश कर दिया है तो दूसरी ओर भाजपा/NDA में मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों की बड़ी फौज है जिसकी वजह से PM मोदी के नाम पर ही राजनीति करने की शंखनाद की गई है। भाजपा ने ''**बटेंगे तो कटेंगे**'' की शब्दों का बाण तो चलाया लेकिन हेमंत सरकार की ''**मईया योजना**'' के सामने कितना कारगर साबित होगा यह तो मतगणना के दिन ही स्पष्ट हो पायेंगा। कहने के लिए INDIA गठबंधन में झामुमो के साथ कांग्रेस और राजद भी मजबूती के साथ है लेकिन झारखंड में झामुमो का प्रभाव इनदोनों पार्टियों से अधिक है नहीं NDA में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन आजसू, जदयू के सामने घुटने टेकने पर मजबूर दिखती है, साथ ही आदिवासी मुख्यमंत्री बनने की लालच रखने वाले उम्मीदवार की आपसी कलह के बीच एक और आदिवासी मुख्यमंत्री उम्मीदवार चंपई सोरेन का भाजपा में शामिल होने की वजह से BJP खुद के बुने जाल में फंसती दिख रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से हटाये जाने के कारण चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होकर हेमंत सोरेन को उखाड़ फेकने के लिए पूरी ताकत झोकने को तैयार हो गये लेकिन BJP के भीतर भयंकर गृहयुद्ध की स्थिति को नहीं समझ सके कि वहां पहले से ही दंजनों उम्मीदवार हैं और तो और JDU सरयू राय को CM देखना चाहती है तो आजसू के सुदेश महतो भी खुद को CM की तरह अपना अकड़ दिखा रहे हैं जिसकी वजह से सीट को लेकर भी आपस में विवाद है। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव एवं झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे गठबंधन राजनीति को नई दिशा देगी तथा विवादस्पद बयान का किस राज्य में क्या असर होगा इसपर सभी दल अपनी-अपनी जीत को सुनिश्चित करने में लगे हैं। मईया योजना का काउंटर करने के लिए BJP ने भी योजना बनाई लेकिन पहले से पैसा ले रहीं महिलाएं किसके पक्ष में Vote डालेंगी यह तो मतदान के दिन ही पता चलेगा की जनता ने किसके पक्ष में फैसला लिया है। सत्ता प्राप्ति के लिए राजनेताओं के गिरते सोच एवं राजनीतिक पत्तन की वजह से आवाम की टैक्स बढ़ता जा रहा है लेकिन विकास की पटरी मजबूत नहीं हो रही है। योजनाओं के नाम पर जमकर महालूट किया जा रहा है और देश की जनता को धर्म, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार की राजनीति में फंसाकर वोट हासिल किया जा रहा है। प्रकृति के साथ झारखंड में जिस प्रकार खिलवाड़ हो रहा है उसपर लगाम कसने की कवायद के बजाय इसको और सुनियोजित ढंग से लूटा जाये उसके जुगाड़ में सभी पार्टियां लगी रहती है। 2019 से लेकर 2024 तक हेमंत सोरेन की सरकार पर मुश्किलों का पहाड़ टूटता रहा है ऐसे में 2024 के चुनाव के नतीजे ही बतायेंगे की लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड की जनता ने क्या मिजाज बनाया है। झारखंड के सभी 24 जिलों में मईया योजना वास्तव में वोटरों का मिजाज INDIA गठबंधन से कहीं ज्यादा JMM पर भरोसा बढ़ा है। रघुवर दास सरकार में बढ़ी अफसरशाही पर लगाम कसने के लिए ही हेमंत सोरेन की सरकार का दोबारा वापस होना तय माना जा रहा है। 23 नवम्बर 2024 को यह तय हो जायेगा कि झारखंड किसका होगा।

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

वर्ष:- 14, अंक:- 161 माह:- नवम्बर 2024 रू. 10/-

Editor

Brajesh Mishra 9431073769
6206889040
8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Principal Editor

Arun Kumar Banka 7782053204
Nilendu Kumar Jha 9431810505

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad 9308815605

General Manager (Advertisement)

Manish Kamaliya 6202340243
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra 8873004350
S. N. Giri 9308454485

Asst. Editor

Mithilesh Kumar 9934021022
Sashi Ranjan Singh 9431253179
Rajeev Kumar Shukla 7488290565
Kamod Kumar Kanchan 8971844318

Sub. Editor

Arbind Mishra 6204617413
Prasun Pusakar 9430826922
Brajesh Sahay 7488696914

Bureau Chief

Sanket kumar Jha 7762089203
Sagar Kumar 9155378519

Bureau

Sridhar Pandey 9852168763
Sonu Kumar 8002647553

Photographer

Mukesh Kumar 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 9868700991

झारखण्ड हेड

ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 9433567880
9339740757

मध्यप्रदेश हेड

अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

छत्तीसगढ़ हेड

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड

निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

उत्तराखण्ड हेड

आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड

आवश्यकता है

गुजरात हेड

आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

पंजाब हेड

आवश्यकता है

हरियाणा हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

उड़ीसा हेड

आवश्यकता है

आसाम हेड

आवश्यकता है

हिमाचल हेड

आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
मो०- 9868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 9433567880, 9339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय त्तल,
फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 9308815605

मध्यप्रदेश कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार पाठक
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
मो०- 8109932505,

विशेष प्रतिनिधी

भारती मिश्र 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,
मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

अक्टूबर 2024

मुख्यमंत्री

मिश्रा जी,

मैंने केवल सच टाइम्स पत्रिका के अक्टूबर 2024 अंक का संपादकीय ''**2024-29 झारखंड का कौन होगा मुख्यमंत्री**'' पढ़कर सटीक जानकारी प्राप्त हुई। आपका संपादकीय निष्पक्ष एवं निर्भिक होता है और बिना किसी दल की चाटुकारिता किए बगैर लिखते हैं जिसकी वजह से खबर की विश्वसनीयता बरकरार है। आपका संपादकीय वास्तव में लोगों की आंख खोलता है और ज्वलंत मुद्दे को पूर्ण बेबाकी से लिखते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और कौन मुख्यमंत्री होगा आपने आलेख में ईशारे में स्पष्ट तौर लिख दिया है। ऐसे संपादकीय से पत्रिका मजबतू होती है।

● **प्रमोद पंडा, टावर चौक, देवघर, झा०**

अलविदा

संपादक महोदय,

मैं केवल सच टाइम्स पत्रिका का नियमित पाठक हूं। अक्टूबर 2024 में प्रकाशित अमित कुमार की खबर ''अलविदा रतन टाटा'' वास्तव में सराहनीय, संग्रहनीय और पठनीय है। भारत के लाल रतन टाटा के जीवन वृत को बहुत ही खूबसूरती के साथ पाठकों के बीच सजाकर रखा गया है। रतन टाटा की सादगी और महादानी व्यक्तित्व को आपकी पत्रिका के द्वारा सच्ची श्रद्धांजलि दी गयी है। रतन टाटा किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे हैं और भारत देश के विभिन्न प्रकार के विपदाओं में रक्षक की भूमिका में खड़े रहे हैं। कोरोना काल हो या आर्थिक मंदी का दौर रतन टाटा ने देश का रत्न होने का प्रमाण दिया है।

● **जयशंकर सिन्हा, सेक्टर-4, बोकारो, झारखंड**

नायाब सिंह सैनी

संपादक महोदय,

अक्टूबर 2024 अंक में देश के हरियाणा राज्य में भाजपा की सरकार बन चुकी है तथा नायाब सिंह सैनी अब खेवनहार की भूमिका को अदा करेंगे। भाजपा पंजाब में हार का बदला हरियाणा में ले चुकी है और बटेंगे तो कटेंगे की युक्ति काम कर गयी है। आपकी पत्रिका अगर रंगीन पृष्ठों में प्रकाशित होगी तो इसकी महत्ता और बढ़ जायेगी। देश के विभिन्न राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों को प्राथमिकता के साथ बिना लाग-लपेट की खबर को प्रकाशित करती है जो काबिले तारिफ है। यह अंक कई मामले में बेहतर है तथा रतन टाटा की पूरी खबर को पढ़कर मन विभोर हो गया। संघ की खबर को भी पत्रिका ने सही स्थान दिया है।

● **बिहार सहाय, अशोक नगर, नई दिल्ली**

श्रद्धांजलि

मिश्रा जी,

सही विषय को प्राथमिकता एवं प्रमुखता से स्थान देने की वजह से केवल सच टाइम्स की अपनी मजबूत पहचान है। टाटा ग्रुप के प्रधान रतन टाटा की मृत्यु की खबर से पूरा देश एवं दुनिश में शोक का लहर है। हर भारतीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहा है क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली रहा है कि उनसे नहीं मिलने के बाद भी लोगों में उनके प्रति पारिवारिक लगाव है। देश के विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवा के लिए अस्पताल तो मुम्बई में कैंसर का हॉस्पीटल खोलकर भारत का अंतिम आदमी को सेवा मिल सकता है की उम्मीद को जिवंत कर दिया है। पूरे देश की आंखे नम है और सभी लोगों ने रटन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। आपकी पत्रिका को धन्यवाद स्थान देने के लिए।

● **महेश सक्सेना, पाया न.-60, राजाबाजार, पटना**

एक पर एक

मिश्रा जी,

अक्टूबर 2024 में संजय सिन्हा की '**बहराईच की बर्बरता**'' की खबर पढ़कर बहुत पीड़ा हुई की भारतीय समाज किस दिशा में जा रहा है। दूसरी खबर ''**पूर्व मंत्री सिद्दकी की गोली मारकर हत्या**'' ने महाराष्ट्र की सरकार को धर्मसंकट में डाल दिया है तथा फिल्म जगत में लौरेंस बिश्नोई की ताकत से लोग डर रहे है और अन्य राजनेता भी इस मामले में टांग अड़ाने पर टारगेट पर हैं जिसमें बिहार के पप्पु यादव भी शामिल हैं। मंत्री सिद्दकी का घोटाला को लेकर भी हत्या का मामला गर्म है। केवल सच टाइम्स पत्रिका को लौरेंस बिश्नोई पर मजबूत खबर लिखना चाहिए कि कैसे एक लड़का अपराध के क्षेत्र में शामिल हुआ।

● **महेन्द्र यादव, बाबू बाजार, कोलकात्ता, पं.बं**

चुनावी ऐलान

संपादक जी,

केवल सच टाइम्स पत्रिका का अक्टूबर 2024 अंक को पढ़कर सटीक जानकारी हुई की झारखंड विधानसभा चुनाव कब होगा और राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार अपनी सीट जीतेगी और सरकार बनायेगी। ''**चुनावी ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज**'' में आदिवासी बहुल प्रदेश झारखंड की समुचित विकास एवं गतिविधियों को केन्द्रीत करके खबर को लिखा गया है जो पठनीय एवं सोचनीय है। इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का एक उम्मीदवार है तो एनडीए में मुख्यमंत्री का आधा दर्जन चेहरा है जिसके वजह से पीएम मोदी भी खुद असमंजस में है कि झारखंड की बाजी जितना आसान नहीं होगा। सटीक एवं जागरूक करने वाला खबर।

● **डी. के. सिंह, टावर चौक, देवघर, झारखंड**

अन्दर के पन्नों में

27

Conversion only for reservation..... 33

36

38

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका
एवं 'केवल सच टाइम्स'
एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020
फोन- 0612/3504251

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी
'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''
9060148110
sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
व्यवसायी
पटना, बिहार
7360955555

एक नजर

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
  e-mail:- kewalsach@gmail.com,
  editor.kstimes@rediffmail.com
  kewalsach_times@rediffmail.com
- स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**
- पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- सभी पद अवैतनिक हैं।
- विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
- फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
- कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।

A/C No.	:-	20001817444
BANK	:-	State Bank Of India
IFSC Code	:-	SBIN0003564
PAN No.	:-	AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of "APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

Registered Under the Indian Society Act 21, 1880

East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020

Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077

E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com

Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

APNA GHAR

Now in the State of Bihar & Jharkhand

Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence in the lives of many Sr. Citizens.

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

A/C No.	-	**0600010202404**
Bank Name	-	**United Bank of India**
IFSC Code	-	**UTBIOKKB463**
Pan No.	-	**AAAAK9339D**

महाराष्ट्र में महायुति ने जीती 230 सीटें, एमवीए 46 पर सिमटी

● अमित कुमार

''मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा''। आज से ठीक 5 साल पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में यह शेर कहा था। तारीख थी 1 दिसंबर 2019 और ठीक पांच साल बाद फडणवीस ने वो कर दिखाया जिसके संकेत उन्होंने दिया था। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर महाराष्ट्र की राजनीति में अपना लोहा मनवाने वाले दिग्गज भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाये गये। हैं। वह इससे पहले भी 2 बार इस पद पर रह चुके हैं। 20 नवंबर के विधानसभा चुनाव में भाजपा के निर्णायक प्रदर्शन के बाद 54 वर्षीय फडणवीस को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया।

इसी के साथ उनके तीसरी बार राज्य की बागड़ोर संभालने की राह तैयार हो गई। फडणवीस का राजनीतिक उत्थान 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले शुरू हुआ, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह का समर्थन हासिल किया। फडणवीस की राजनीतिक यात्रा उल्लेखनीय रही है। इस दौरान एक गुमनाम पार्षद से लेकर नागपुर के सबसे युवा महापौर बनने का गौरव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने भाजपा के भीतर एक प्रमुख नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। उल्लेखनीय बात यह है कि वह शिवसेना के मनोहर जोशी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे ब्राह्मण हैं। फडणवीस का राजनीतिक उत्थान 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले शुरू हुआ, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह का समर्थन हासिल किया। मोदी ने एक चुनावी रैली में फडणवीस को 'नागपुर का देश को उपहार' बताया था, जो उनके फडणवीस में विश्वास को दर्शाता था। हालांकि मोदी ने 2014 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में धुआंधार प्रचार अभियान चलाया था, लेकिन चुनावों में पार्टी की अभूतपूर्व जीत का कुछ श्रेय तत्कालीन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष फडणवीस को भी गया था। जनसंघ और बाद में भाजपा के नेता रहे गंगाधर फडणवीस के पुत्र देवेंद्र ने युवावस्था में राजनीति में कदम रखा और 1989 में आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। पूर्व भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी दिवंगत गंगाधर को अपना 'राजनीतिक गुरु' कहते हैं। देवेंद्र फडणवीस 22 वर्ष की आयु में नागपुर नगर निगम के पार्षद बने तथा 1997 में 27 वर्ष की आयु में इसके सबसे युवा महापौर बने। फडणवीस ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1999 में लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीते। नवम्बर में हुए चुनाव में उन्होंने अपनी नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट बरकरार रखी। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में कई नेताओं के विपरीत फडणवीस पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। महाराष्ट्र के सबसे मुखर राजनेताओं में से एक फडणवीस को सिंचाई घोटाले को लेकर तत्कालीन कांग्रेस-राकांपा सरकार को मुश्किल में डालने का श्रेय भी दिया जाता है। फडणवीस को 2019 के विधानसभा चुनाव में तब झटका लगा जब अविभाज्य शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद को लेकर चुनाव पूर्व गठबंधन से हाथ खींच लिया और भाजपा नेता का 'मैं वापस आऊंगा' उद्घोष अधूरा रह गया। फडणवीस ने 23 नवंबर, 2019 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद संभाला। हालांकि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने से पहले ही फडणवीस ने 26 नवंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वह महज तीन दिन मुख्यमंत्री रहे। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे बाद में मुख्यमंत्री बने, लेकिन जून 2022 में वरिष्ठ शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे द्वारा पार्टी विभाजित करने के बाद उन्होंने (ठाकरे ने) इस्तीफा दे दिया और बाद में शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। शिवसेना में बड़े पैमाने पर उठापटक और ठाकरे के पद छोड़ने के बाद कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का दावा था कि इस घटनाक्रम में फडणवीस का हाथ है और वह मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि भाजपा की दूसरी योजनाएं थीं और अनिच्छुक फडणवीस को उपमुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए कहा गया। उपमुख्यमंत्री के रूप में पिछले ढाई वर्षों का उनका कार्यकाल खास रहा और 23 नवंबर के विधानसभा चुनाव परिणाम उनके लिए बहुप्रतीक्षित उपलब्धि की तरह आए। बता दें कि शपथ ग्रहण के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उद्योग तथा फिल्म जगत की

कई प्रमुख हस्तियां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुईं। भाजपा नेता फडणवीस दक्षिण मुंबई के विशाल आजाद मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। समारोह में योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), नीतीश कुमार (बिहार), चंद्रबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश), पुष्कर सिंह धामी (उत्तराखंड), नायब सिंह सैनी (हरियाणा), भूपेंद्र पटेल (गुजरात) और प्रमोद सावंत (गोवा) सहित राजग शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और रामदास आठवले भी इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद थे। उद्योगपति मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिड़ला तथा अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, माधुरी दीक्षित-नेने, संजय दत्त और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर भी समारोह में उपस्थित थे।

बहरहाल, शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री की अटकलों के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने फडणवीस को फोन कर प्रचंड जीत की बधाई दी। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया कि ज्यादा सीटें मिलने का मतलब यह नहीं है कि सीएम भी उसी दल का होगा। उन्होंने कहा कि तीनों दल यानी भाजपा, शिवसेना और एनसीपी मिलकर सीएम तय करेंगे। हालांकि यह बयान उन्होंने एक मीडियाकर्मी

के सवाल पर जवाब के तौर पर दिया है। उनसे पूछा गया था कि क्या यह पहले से तय हुआ था कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी सीएम उसी दल का बनेगा। इसके जवाब में शिंदे ने जवाब दिया कि ज्यादा सीटें मिलने का अर्थ सीएम नहीं है। सभी मिलकर तय करेंगे सीएम। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत महायुति गठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करते हुए 288 सदस्यीय विधानसभा की 230 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस नीत महा विकास आघाडी (एमवीए) महज 46 सीटों पर सिमटकर रह गई। चुनाव आयोग ने घोषणा की कि भाजपा ने 132 सीटें जीती हैं, शिवसेना ने 57 सीटें जीती हैं जबकि राकांपा को 41 सीटें मिली हैं। एमवीए में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के उम्मीदवारों ने 10 सीटें जीतीं, कांग्रेस ने 16 सीटें जीतीं जबकि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने 20 सीटें जीतीं। कांग्रेस ने उपचुनाव के आए नतीजे में महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा बरकरार रखी है, जहां उसके उम्मीदवार रवीन्द्र चव्हाण ने भाजपा के संतूकराव हम्बर्डे को 1457 मतों से हराया। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीटें पर शानदार जीत हासिल की। ऐसी खबरें थीं कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह दक्षिण

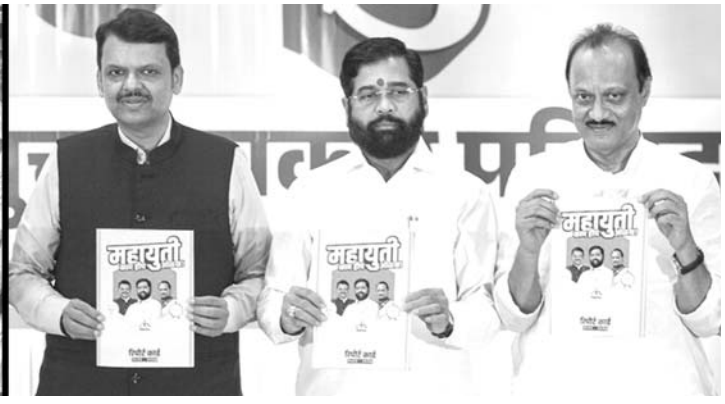

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो सकता है, जहां 10 साल पहले फडणवीस ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के विजेताओं में भाजपा के कालिदास कोलंबकर शामिल हैं जिन्होंने वडाला निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना (यूबीटी) की श्रद्धा जाधव को 24,973 वोट से हराया और लगातार 9वीं बार विधायक बने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अजित पवार ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण और बालासाहेब थोराट अपने-अपने क्षेत्रों में हार गए। राज्य कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने साकोली सीटें से 208 मतों से जीत दर्ज की। विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार ने ब्रह्मपुरी से भाजपा के उम्मीदवार कृष्णलाल सहारे को 13971 मतों से हराया। वही समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जन सुराज्य शक्ति के 2, राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी के 1, राष्ट्रीय समाज पक्ष के 1, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 1, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 1, किसान और श्रमिक पार्टी ऑफ इंडिया के 1, राजर्षि शाहू विकास आघाडी के 1 और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। शिंदे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक थे और ये यह दिखाते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना किसकी पार्टी है। फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है और महायुति के नेता इस मुद्दे पर मिलकर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि नतीजों से पता चलता है कि राज्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का समर्थन करता है। उन्होंने महिला मतदाताओं को भी धन्यवाद दिया। फडणवीस ने कहा कि फर्जी बयानबाजी करने और धर्म के आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के विपक्ष के प्रयासों को जनता ने नाकाम कर दिया।

गौरतलब है कि दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फडणवीस को अपना 'परम मित्र' बताया। मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, यह पिछले 50 वर्षों में किसी भी पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन की सबसे बड़ी जीत है। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू जी महाराज, महात्मा फुले, सावित्री बाई फुले, बाबा साहेब अंबेडकर, वीर सावरकर, बाला साहब ठाकरे. .. ऐसे महान व्यक्तित्व की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री-पोल अलायंस के लिए सबसे बड़ी जीत है। ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है और भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये भाजपा के गवर्नेंस मॉडल पर मुहर है। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है, महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है, महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। वहीं, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी हैं, निगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है, आज परिवारवाद की हार हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की जीत हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हालिया चुनावों में विकास के संदेश की जीत हुई है जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा फैलाया गया झूठ और विश्वासघात की राजनीति को हार का सामना करना पड़ा है। यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय में पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव और विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावों में विभाजनकारी ताकतों, नकारात्मक राजनीति और वंशवाद की हार हुई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने स्थिरता के लिए मतदान किया है और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने वालों को सबक सिखाया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र चुनाव से एकता का संदेश मिला है और 'एक हैं तो सुरक्षित हैं' के नारे को समर्थन हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि

एक हैं तो सुरक्षित हैं का नारा पूरे देश के लिए 'महामंत्र' बन गया है और इसने उन लोगों को दंडित किया है जो देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटना चाहते थे। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों ने भाजपा को वोट दिया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके तंत्र ने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ फैलाकर वे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को छोटे-छोटे समूहों में बांट सकते हैं। यह उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने विभाजनकारी तत्वों को धूल चटा दी है। कांग्रेस और उसके सहयोगी देश के बदलते मूड को समझने में विफल रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदाता अस्थिरता नहीं चाहते हैं और वे राष्ट्र प्रथम में विश्वास करते हैं तथा 'कुर्सी प्रथम' का सपना देखने वालों को पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मतदाताओं ने कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में किए गए झूठे वादों के आधार पर भी कांग्रेस का मूल्यांकन किया। मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में न तो उनके झूठे वादे काम आए और न ही उनका खतरनाक एजेंडा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव यह भी दर्शाता है कि भारत में केवल एक संविधान चलेगा और वह संविधान देश के लोगों को बी. आर. अंबेडकर ने दिया था। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस वालों और उनके साथियों को भी कहता हूं कि कान खोलकर सुन लो... अब दुनिया की कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबा देती है। आज महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा है। देश के हर राज्य का वोटर दूसरे राज्यों की सरकारों का आकलन भी करता है। वो देखता है कि जो राज्य में बड़े-बड़े वादे करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस दूसरे राज्यों में कैसी है। महाराष्ट्र की जनता ने भी देखा कि कर्नाटक, तेलंगाना व हिमाचल में कांग्रेस सरकारें कैसे जनता से विश्वासघात कर रही। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की और उन्हें राज्य में महायुति की जीत पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि एकजुट होकर हम और भी ऊंची उड़ान भरेंगे! एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए महाराष्ट्र के अपने भाइयों-बहनों, खासकर युवाओं और महिलाओं का दिल से आभार...। मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारा गठबंधन महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि मैं झारखंड के लोगों को हमारे प्रति उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। हम लोगों के मुद्दों को उठाने और राज्य के लिए काम करने में हमेशा सबसे आगे रहेंगे। मैं JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन को भी राज्य में उनके प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम महाराष्ट्र के सभी नागरिकों के आभारी हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी में महाराष्ट्र के विश्वास को दर्शाता है। मुख्यमंत्री शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तीनों पार्टी मिलकर तय करेंगी कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के लिए राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि गठबंधन को इतना बड़ा बहुमत देकर लोगों ने संविधान के फर्जी शुभचिंतकों की दुकानें बंद करा दीं। केंद्रीय मंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि जय महाराष्ट्र! इस ऐतिहासिक जनादेश के लिए महाराष्ट्र की जनता का कोटि-कोटि वंदन। भाजपा नेता ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले और वीर सावरकर की पुण्यभूमि महाराष्ट्र ने विकास के साथ-साथ संस्कृति और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने वाले महायुति गठबंधन को इतना प्रचंड जनादेश देकर भ्रम और झूठ के सहारे संविधान के नकली हितैषी बनने वालों की दुकान पर ताला लगा दिया है। वही देवेंद्र फडणवीस की मां सरिता फडणवीस ने भी महायुति के प्रदर्शन पर खुशी जताई और अपने बेटे को प्रधानमंत्री मोदी का पसंदीदा बताया। 'लाडकी बहिन' पर उन्होंने कहा कि मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन इस योजना के जरिए अब मुझे कई

बेटियां और उनकी शुभकामनाएं मिल गई हैं। महायुति में भाजपा ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, शिवसेना ने 81 सीटों पर और अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने 59 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। एमवीए गठबंधन में कांग्रेस ने 101, शिवसेना (यूबीटी) ने 95 और राकांपा (एसपी) ने 86 उम्मीदवार उतारे।

सनद् रहे कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन, 4 जून को कांग्रेस मुख्यालय स्थित पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक के कमरे में नेताओं का जमघट लगा था और एक तरह से जश्न का माहौल था, लेकिन इसके करीब 6 महीनों बाद 23 नवंबर को इस कमरे में वीरानी छाई हुई थी। यह वीरानी सिर्फ एक कमरे में नहीं थी, बल्कि लगभग समूचे मुख्यालय में थी और इसकी वजह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी और उसके गठबंधन की करारी हार थी। पिछले कुछ चुनावों से यह देखा गया है कि नतीजों वाले दिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड स्थित वासनिक के कमरे में जमा होते हैं और वहीं पर उनका संवाद भी होता है, लेकिन 23 नवम्बर को ऐसा कुछ नहीं था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस और महा विकास आघाडी (एमवीए) के पिछड़ने के बाद पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता मुख्यालय नहीं पहुंचे और दोपहर 12 बजे तक तस्वीर साफ होने पर कार्यकर्ताओं-समर्थकों की बची-खुची

उम्मीद भी खत्म हो गई तथा वे भी मुख्यालय से रवाना होने लगे। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने वाले कुछ नेताओं में पार्टी की सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत शामिल थीं। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे दिवंगत अहमद पटेल की पुत्री मुमताज पटेल भी टेलीविजन चैनलों को प्रतिक्रिया देती दिखाई दीं। पार्टी कवर करने वाले पत्रकार प्रतिक्रिया के लिए वरिष्ठ नेताओं की राह देखते रहे। एक मीडियाकर्मी ने कहा कि अभी 12 बज रहे हैं, सुबह छह बजे से यहां हूं और अब तक वे बड़े चेहरे यहां नहीं दिखे जो अक्सर यहां आते हैं। महाराष्ट्र की हार के कारण यह स्वाभाविक भी लगता है। कांग्रेस मुख्यालय में सिर्फ वरिष्ठ नेताओं के कमरे ही खाली नहीं थे, बल्कि पार्टी मुख्यालय के बाहर, प्रांगण और कैंटीन में भी आम दिनों की तरह ही थोड़ी-बहुत हलचल थी। पार्टी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर निराशा साफ देखी जा सकती थी। इस बीच कुछ कार्यकर्ता आपसी बातचीत में ईवीएम में खेल होने की बात करते सुने जा सकते थे। कांग्रेस की कैंटीन में भी बालूशाही, लड्डू और रसगुल्ले जैसी मिठाइयां बनाकर रखी हुई थीं, लेकिन शायद इनके उतने खरीददार नहीं थे, जिसकी उम्मीद कैंटीन चलाने वालों को रही होगी। पार्टी के एक नेता ने कहा कि हरियाणा के बाद एक बार फिर से हमारी उम्मीदें टूटी हैं। झारखंड के नतीजों से थोड़ी राहत जरूर मिली है। काश दोनों राज्यों में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार बनती। वही कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि जब तक ईवीएम है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ईवीएम का जीत के लिए इस्तेमाल बड़ी चतुराई से करते हैं। हर जगह नहीं करते क्योंकि जनता को शक हो जाएगा। महाराष्ट्र के नतीजे को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं अपनी पार्टी से भी कहूंगा। सड़क पर उतरने और आंदोलन का वक्त है। ईवीएम हटाना चाहिए। महाराष्ट्र में ईवीएम का दुरुपयोग किया, झारखंड में नहीं किया। सेलेक्टिव किया। झारखंड में भी इनकी मेहरबानी।

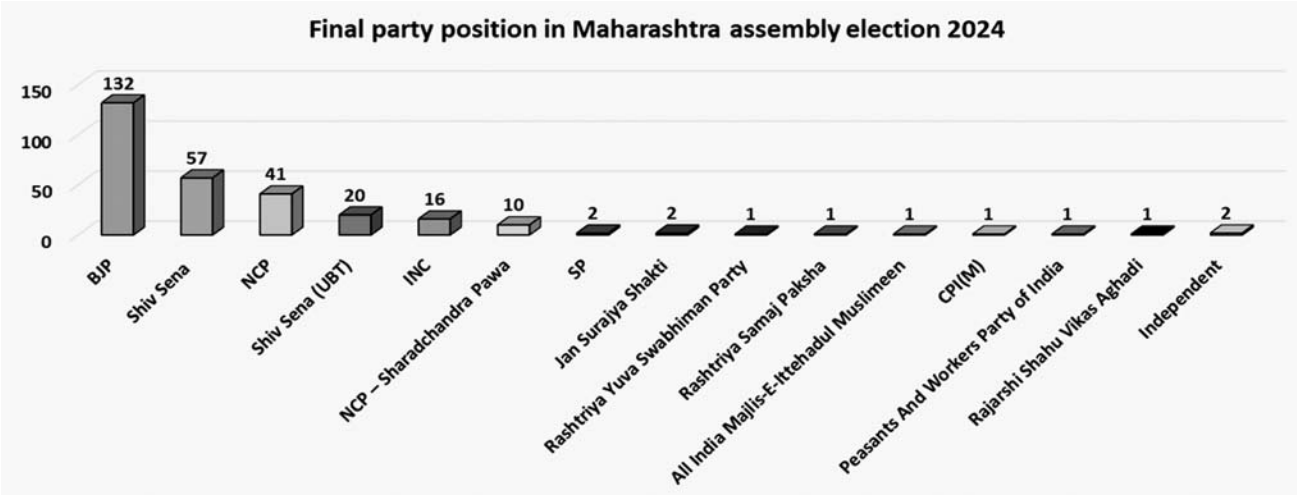

महाराष्ट्र में जितना था इनको क्योंकि अडानी को बचाना था। संजय राउत ठीक कह रहे हैं। ईवीएम का नतीजा है जनता का नहीं। स्वीकार नहीं करना चाहिए नतीजा। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच शिवसेना-यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। बता दें कि इस समय महायुति 215 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं एमवीए 61 सीटों पर आगे है। संजय राउत ने कहा कि ये लोगों की राय नहीं है। ये फैसला, जनता का फैसला नहीं है, दो दिन पहले अडाणी के खिलाफ वारंट निकला है, उसमें बीजेपी की पूरी पोल खुल गई, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब किया गया है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि मुंबई गौतम अडाणी के जेब में जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम था। हमारी 4-5 सीटें इन्होंने चोरी की है। हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी, जिस राज्य में

सबसे बड़ी बेईमानी होती है, उस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। दिगर बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की वजह से नहीं, बल्कि इसके नेतृत्व के खराब प्रबंधन की वजह से करारी हार मिली और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से कहा कि वह वोटिंग मशीन की जगह राहुल गांधी को 'बदलने' पर विचार करें। ईवीएम पर कांग्रेस अध्यक्ष की हालिया टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधते हुए भाजपा के लोकसभा सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि खरगे यदि ईवीएम, निर्वाचन आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, न्यायपालिका और मोदी सरकार नहीं चाहते हैं तो राहुल गांधी को लेकर 'मंगल ग्रह' पर जा सकते हैं और वहां खुशी से रह सकते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी की प्रतिक्रिया खरगे द्वारा चुनावों में मतपत्र के उपयोग की वापसी की मांग करने के एक दिन बाद आई है। खरगे ने इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर एक ठोस अभियान का आह्वान भी किया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने तालकटोरा स्टेडियम में 'संविधान रक्षक अभियान' को संबोधित करते हुए कहा था, उन्हें ईवीएम अपने पास रखने दीजिए। हम ईवीएम नहीं चाहते, हम बैलेट पेपर से मतदान चाहते हैं। तब उन्हें पता चलेगा कि उनकी स्थिति क्या है और वे कहां खड़े हैं। पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ईवीएम की

विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार पर अपनी हताशा निकाल रहे हैं। उन्होंने यहां भाजपा मुख्यालय में कहा, समस्या मशीन (ईवीएम) में नहीं है। समस्या नेतृत्व (कांग्रेस) के साथ है। पात्रा ने कहा कि ईवीएम ठीक है, राहुल खराब हैं। राहुल को बदलें, ईवीएम को नहीं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि खरगे ईवीएम, निर्वाचन आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और न्यायपालिका नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप भारत की मौजूदा सरकार भी नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है कि यह एक अच्छी सरकार नहीं है। आप कुछ भी नहीं चाहते हैं। तब मुझे लगता है कि मंगल ग्रह आपके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। कोई नहीं है वहां, आप वहां जाइए, शहजादा को कुर्सी पर बैठाइए और खुशी से जिएं। भाजपा प्रवक्ता ने खरगे पर अपनी टिप्पणी के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यह काफी आश्चर्यजनक है कि मल्लिकार्जुन खरगे ने कल कहा कि ईवीएम के कारण एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों के वोट बर्बाद हो रहे हैं। भाजपा नेता ने पूछा, क्या उन्हें लगता है कि एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब समुदायों के लोगों को ईवीएम का उपयोग करना नहीं आता है? पात्रा ने कहा कि खरगे ने ईवीएम पर टिप्पणी के साथ झारखंड में अपनी पार्टी के सहयोगी दल की जीत पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर क्या आप यह कह रहे हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत एक तरह के कदाचार का नतीजा है और वे जीतने के लायक नहीं हैं। जब आप हारते हैं, तो यह दोषपूर्ण होता है। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ईवीएम को खारिज करे या नहीं, जनता ने पार्टी को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है।

बताते चले कि महाविकास अघाड़ी के तीनों ही दल बुरी तरह फेल रहे जबकि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी (वीबीए) भी राज्य विधानसभा चुनाव में प्रभाव छोड़ने में विफल रही। यहां तक कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। मनसे ने जहां 125 उम्मीदवार उतारे थे, वहीं वीबीए के 200 उम्मीदवार मैदान में थे। मनसे को बड़ा झटका यह है कि पार्टी प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मुंबई की माहिम सीट पर तीसरे स्थान पर चल रहे थे। राजू शेट्टी के नेतृत्व वाले स्वाभिमानी पक्ष ने 19 उम्मीदवार उतारे थे और यह पार्टी भी कोई प्रभाव छोड़ने में विफल रही। यह पार्टी किसानों के बीच, खासकर पश्चिमी महाराष्ट्र में, प्रभाव रखने के लिए जानी जाती है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रुझानों के अनुसार, समाजवादी पार्टी, जन सुराज्य शक्ति और माकपा 2-2 सीट पर आगे चल रही हैं, जबकि एआईएमआईएम, राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष और राजश्री शाहू विकास आघाडी एक-एक सीट पर आगे चल रही थी। 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में कुल 158 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। भाजपा राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। इसके बाद शिवसेना शिंदे और फिर एनसीपी अजित पवार है। सनद् रहे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को बंपर जीत मिली है। इस जीत से सत्तारुढ़ गठबंधन में उत्साह का संचार हुआ है वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति पर भी सवाल उठा दिए हैं। राज्य में 21 महिलाओं ने चुनाव जीतकर विधानसभा का सफर तय किया है। जहां भाजपा महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीट के लिए घोषित नतीजों में 21 महिला उम्मीदवार विजयी रहीं। सबसे ज्यादा 14 महिला उम्मीदवार भाजपा के टिकट पर जीती हैं और इनमें से 10 फिर से निर्वाचित हुई हैं। इन 10 महिलाओं में श्वेता महाले (चिकली), मेघना बोर्डिकर (जिंतूर), देवयानी फरांदे (नासिक मध्य), सीमा हीरे (नासिक पश्चिम), मंदा म्हात्रे (बेलापुर), मनीषा चौधरी (दहिसर), विद्या ठाकुर (गोरेगांव), माधुरी मिसाल (पार्वती), मोनिका राजले (शेवगांव) और नमिता मुंडाडा (कैज) शामिल हैं। भाजपा की चार नई महिला विधायक श्रीजया चव्हाण

(भोकर), सुलभा गायकवाड़ (कल्याण पूर्व), स्नेहा पंडित (वसई) और अनुराधा चव्हाण (फुलंबरी) हैं। शिवसेना के टिकट पर मंजुला गावित (सकरी) और संजना जाधव (कन्नड़) चुनी गई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के टिकट पर सुलभा खोडके (अमरावती), सरोज अहिरे (देओलाली), सना मलिक (अणुशक्तिनगर) और अदिति तटकरे (श्रीवर्धन) ने जीत हासिल की। कांग्रेस की ज्योति गायकवाड़ (धारावी) विपक्ष की ओर से एकमात्र महिला विधायक होंगी। बताते चले कि महायुति ने मराठवाड़ा क्षेत्र की 46 में से 40 सीट जीतीं, जिनमें जालना की सभी 5 सीट शामिल हैं। जालना, नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर जरांगे के आंदोलन का केंद्र रहा है। मराठा आरक्षण आंदोलन के कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनके आंदोलन का कोई असर नहीं होने की चर्चा को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र में 288-सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में महायुति गठबंधन ने 230 सीट जीतकर सत्ता बरकरार रखी। महायुति गठबंधन में भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) भी शामिल हैं। इस वर्ष हुए लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन के खराब प्रदर्शन का श्रेय काफी हद तक जरांगे के आंदोलन को दिया गया था। जरांगे ने विशेष रूप से उपमुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी। जरांगे ने कहा कि कोई यह कैसे कह सकता है कि विधानसभा चुनाव में जरांगे फैक्टर विफल हो गया, जबकि मैंने न तो चुनाव लड़ा और न ही किसी का समर्थन किया? मैंने मराठा समुदाय को इन राजनीतिक दलों के चंगुल से मुक्त कराया। मराठा समुदाय को अपनी पसंद के अनुसार वोट देने की आजादी मिली। मेरा ध्यान मराठाओं को सशक्त बनाने पर है।'' उन्होंने चुनाव परिणामों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 204 मराठा उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं।

वही मंथन भरा सवाल है कि आखिर क्यों शरद पवार का कद महाराष्ट्र की राजनीति में घट गया और उन्हें इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ क्यों महाराष्ट्र की जनता ने एकनाथ शिंदे को जिताकर एक तरह से असली शिवसेना का वारिस घोषित कर दिया। क्या है महाराष्ट्र में महायुति की जीत का पूरा फैक्टर। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में नितीन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस बड़े चेहरे हैं। हालांकि गडकरी सीएम की रेस में नहीं माने जाते हैं। महाराष्ट्र में महायुति की इस जीत के मायने समझने के लिए महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक जानकारों की अपनी-अपनी राय है। लोकमत के संपादक विकास मिश्र ने कहा कि, मैं शुरू से कहता था कि यह परिणाम तय है। लेकिन इस प्रचंडता से यह जीत सामने आएगी इसका अंदाजा नहीं था। जहां तक एक्जिट पोल की बात है तो उस पर इतना यकीन ठीक नहीं है। विकास मिश्र ने बताया कि इस बार महाराष्ट्र में तकरीबन पांच प्रतिशत वोटिंग ज्यादा हुई है। इसके साथ ही महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। इसके पीछे की वजह है लाडकी बहीण योजना ने काम दिखाया। वे बताते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास तो कोई नेता है नहीं, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन जिस तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे का कद घटा है उससे कहा जा सकता है कि यहां की राजनीति में कुछ तो बदल रहा है। इसका मतलब यह माना जाना चाहिए कि महाराष्ट्र की जनता की नजर में एकनाथ शिंदे शिवसेना के असली वारिस हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि जहां तक महाराष्ट्र में सीएम की दावेदारी को लेकर सवाल है तो देवेंद्र फडणवीस प्रमुख दावेदार हैं। इस बात में ज्यादा संशय नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि जब देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं तो फिर शिंदे भी फडणवीस के साथ काम कर सकते हैं। वे फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं। नागपुर में लोकमत के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक जानकार फहीम खान कहते हैं कि महाविकास अघाडी ने नहीं सोचा था कि ऐसे हारेंगे। भाजपा ने जिस तरह से सीटें जीती है बहिण योजना का फायदा मिला। पार्टियों के पारंपरिक चिन्हों को लेकर भी लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है। पिछले ढाई साल में महायुति ने जमकर ब्रांडिंग की। सीएम के लिए कोई पैंच नहीं फंसेगा, देवेंद्र फडणवीस तय नाम है सीएम पद के लिए। अगर सीएम देवेंद्र फडणवीस बनते हैं तो गृह मंत्रालय भी अपने पास रखेंगे क्योंकि इस पद पर रहते हुए उन्होंने बहुत काम किया और पार्टी के लिए। वही नागपुर संघ हेडक्वार्टर से जुडे एक संघ पदाधिकारी का कहला है कि महाराष्ट्र चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की सक्रियता बीजेपी के लिए जमकर फायदेमंद साबित हुई। उन्होंने बताया कि दरअसल संघ काफी पहले से सक्रिय हो गया था। इसके लिए संघ ने अपने करीब 40 अलग अलग सहयोगी संगठनों को जमीन पर उतारा। घर घर संपर्क किया। संघ ने संगठनों के साथ मिलकर मैदान में अपनी छोटी-छोटी टोलियां बनाकर हर गांव और शहर तक अपनी पैठ बनाई और मतदाताओं को अपने पक्ष में किया। संघ से जुड़े

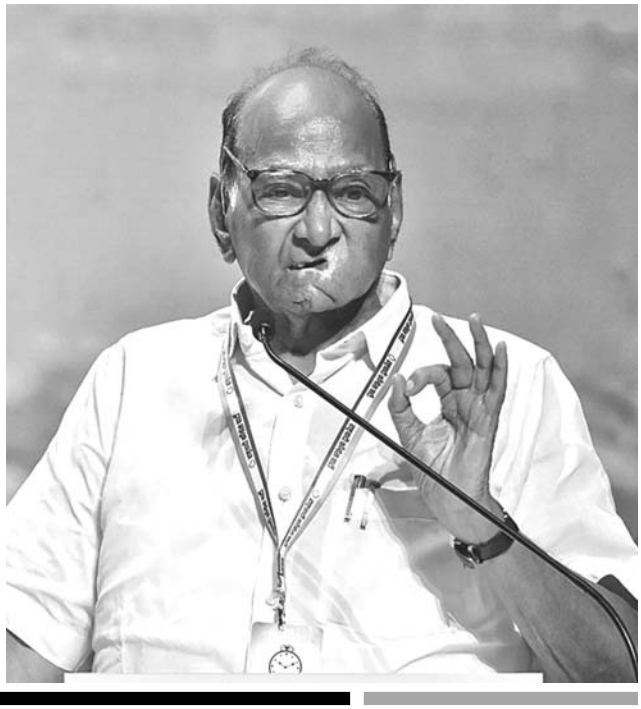

संगठन जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मजदूर संघ, किसान संघ, राष्ट्र सेविका समिति, दुर्गा शक्ति जैसे संगठनों के कार्यकर्ता जागरण मंच के बैनर के तहत घर-घर पहुंचे। इन संगठनों भूमि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, पथराव, दंगा, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही संघ और उसके सहयोगी संगठन ने मतदाताओं को बूथ केंद्र तक ले जाने का दांव बीजेपी के लिए अहम फैक्टर साबित हुआ। वही महाराष्ट्र के जानकारों का मानना है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के चुनाव मैनेजमेंट की कमान संभालने के बाद ग्राउंड स्तर पर बहुत बदलाव हुआ। वहीं पीएम मोदी ने अपनी जनसभाओं के जरिए सियासी माहौल को बदला। बीजेपी ने इस बार विदर्भ पर भी खास ध्यान दिया। विदर्भ में महायुति ने अपनी स्थिति को काफी सुधारा है। इसके अलावा मराठवाड़ा और वेस्ट महाराष्ट्र में बीजेपी ने मराठा आरक्षण आंदोलन के असर को बेअसर करने के लिए हिंदुत्व का आक्रामक दांव खेला। लाडकी बहीण योजना और महिला वोटर्स गेमचेंजर- महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की जीत का बड़ा कारण लाडकी बहना योजना है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्य की महिला वोटरों को साधने के लिए लाडकी बहना योजना का एलान कर दिया है और चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में दिसंबर तक पैसा भेजकर ऐसा कार्ड चला जो चुनाव में उसके लिए ट्रंप कार्ड साबित हुआ। वहीं चुनाव के दौरान महायुति ने सत्ता में वापसी पर लाडकी बहीण योजना की राशि बढ़ाने का एलान कर महिला वोटरों को अपने साथ जोड़ लिया। लबोलुआब है कि एक तरफ शरद पवार और अजित पवार के बीच टूट के बाद जहां शरद पवार का पावर कम हुआ, वहीं महाविकास अघाड़ी में फूट का फायदा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार दो गठबंधन महायुति और महाविकास

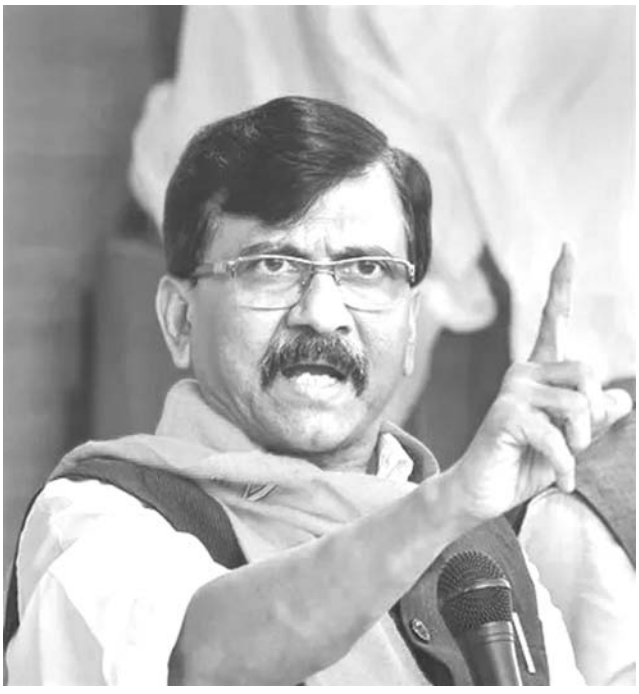

अघाड़ी के बीच सीधा मुकाबला था और चुनाव के दौरान जिस तरह से महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे से लेकर सीएम चेहरे को लेकर तकरार दिखाई दी उसका सीधा फायदा महायुति गठबंधन को मिला। वोटिंग से ठीक पहले जहां महायुति गठबंधन के दो बड़े नेता एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने अपना नाम मुख्यमंत्री चेहरे से पीछे रखा वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे का यह बयान कि महाविकास अघाड़ी को अपना सीएम चेहरा घोषित करना चाहिए, उनकी आपसी खींचतान को बताती है। इसका असर यह हुआ है कि चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों दल के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर एक नहीं हो पाए। कुल मिलाकर आरएसएस की सक्रियता से लेकर लाडकी बहीण योजना, वोट प्रतिशत में इजाफा और महिलाओं का वोट देने के लिए बडी तादात में आगे आना बीजेपी और सहयोगी दलों के लिए बेहद फायदेमंद रहा। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा कि 'लाडकी बहिन' योजना, मतदान में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत में संभवत: भूमिका निभाई। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र को पता है कि एनसीपी किसकी है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन वह पार्टी को फिर से मजबूत करेंगे। सक्रिय राजनीति से अलग होने के बारे में पूछे गए सवाल पर पवार ने कहा कि वह और उनकी पार्टी के सहयोगी इस बारे में फैसला करेंगे। सतारा जिले के कराड शहर में पत्रकारों से बातचीत में शरद पवार ने स्वीकार किया कि उनके भतीजे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने उनकी पार्टी (राकांपा-एसपी) से अधिक सीट पर जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा, ''हर कोई जानता है कि राकांपा की स्थापना किसने की थी।'' उन्होंने कहा कि लाडकी बहिन योजना और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण ने इसमें भूमिका निभाई। महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी महाराष्ट्र में महायुति की जीत का कारण हो सकती है। हम हार के कारणों पर विचार-विमर्श करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। पवार ने कहा कि राकांपा (शरदचंद्र पवार) नए नेतृत्व की नयी ऊर्जा के साथ लोगों के बीच जाएगी। ईवीएम पर पूछे गए सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि वह ईवीएम के बारे में तभी बोलेंगे जब उनके पास आधिकारिक आंकड़े होंगे। एक दिन पहले शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने महायुति के पक्ष में आए बड़े जनादेश के पीछे ''गड़बड़ी'' का संदेह जताया था। पवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक जीवन की सबसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उनके नेतृत्व वाली राकांपा (एसपी) को 288 सदस्यीय विधानसभा में केवल 10 सीटें मिलीं, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा को 41 सीटें मिलीं। महायुति ने भारी जीत हासिल की जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 132, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 और राकांपा ने 41 सीटें जीतीं। इसके विपरीत, विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) 46 सीटों पर ही सिमट गया। राकांपा (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा, ''महा विकास आघाडी गठबंधन ने बहुत मेहनत की, लेकिन वांछित परिणाम नहीं मिले, भले ही लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान एमवीए को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।'' उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद एमवीए अधिक आश्वस्त था। पवार ने यह भी कहा कि और अधिक काम किए जाने की जरूरत है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह चुनाव परिणामों से हैरान रह गए, पवार ने कहा, ''कल चुनाव परिणाम घोषित किए गए। आज मैं कराड में हूं। जो लोग हतोत्साहित हुए, वे घर बैठ गए होंगे।'' पवार ने यह भी कहा कि बारामती में अजित पवार के खिलाफ अपने पोते युगेंद्र पवार को मैदान में उतारना कोई गलत फैसला नहीं था, क्योंकि किसी को तो चुनाव लड़ना ही था। अजित पवार ने बारामती में युगेंद्र को एक लाख से अधिक मतों के अंतर से हराकर आठवीं बार जीत हासिल की। शरद पवार ने कहा, ''अजित पवार और युगेंद्र पवार की तुलना नहीं की जा सकती। हम इस तथ्य से अवगत थे।''

बहरहाल, फडणवीस के सीएम शपथ ग्रमण से पहले महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर महायुति के नेताओं की बैठक हुई थी। यह करीब ढाई घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर चर्चा हुई थी। बैठक में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी मौजूद रहे। इस मीटिंग से पहले अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच करीब आधे घंटे तक अकेले में बैठक हुई थी। देवेन्द्र फडणवीस को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से हैं और पहली बार 2014 में मुख्यमंत्री बने थे और फिर 2019 में कुछ समय के लिए फिर से मुख्यमंत्री बने। सूत्रों ने कहा कि अगर आरएसएस का हुक्म चलता है तो फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की संभावना उज्ज्वल है। दूसरी तरफ बता दें कि एकनाथ शिंदे सीधे अमित शाह के कृष्ण मेनन मार्ग स्थित आवास पर पहुंचे, जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले से मौजूद थे। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजित पवार गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंच गए हैं। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह राज्य में सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह द्वारा लिए गए फैसले का पालन करेंगे। किन्तु महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की महाविजय के कई दिन हो चुके हैं किन्तु नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा और इसका फैसला कब होगा, यह सवाल मुंबई से दिल्ली तक गूंज रहा था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर थी कि शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सरकार को बाहर से समर्थन देने की बात कह कर अपने तेवर दिखा रहे थे। शिंदे गुट ने साफ कर दिया है कि बड़ी पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा जाएगा, ऐसा कोई फॉर्मूला पहले से तय नहीं था। बताते चले कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की रेस में भाजपा की ओर से देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है, तो वहीं दूसरी मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है, इसी को लेकर सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ था। दरअसल विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया था और चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ने खुद को मुख्यमंत्री की रेस में नहीं माना था। वहीं विधानसभा चुनाव नतीजों में महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद शिवसेना और भाजपा दोनों ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोंकी थी। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के नेता जहां चुनाव में गठबंधन की जीत का श्रेय मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को बता रहे है, वहीं भाजपा इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और देवेंद्र फडणवीस की मेहनत को बता रहे थे। यहीं कारण है कि दोनों ही दलों के नेता और कार्यकर्ता अपने-अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बने गतिरोध को खत्म करने के लिए भाजपा अब गठबंधन के तीनों सहयोगी दलों के साथ चर्चा कर रही थी। बता दें कि महाराष्ट्र में नए सीएम चेहरे के चयन में देरी का एक बड़ा कारण जातीय समीकरण भी माना जा रहा था। महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठा आंदोलन तेज पकड़ता जा रहा है, ऐसे में प्रचंड जीत के बाद भी भाजपा के लिए मराठा चेहरे एकनाथ शिंदे को दरकिनार करना आसान नहीं होगा। वहीं भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री के दावेदार देवेंद्र फडणवीस अगड़े समुदाय से आते है और उनकी पार्टी का संगठन में मजबूत पकड़ है, ऐसे में अगर भाजपा किसी ओबीसी चेहरे को आगे करती है तो उसके सामने यह भी उतना आसान नहीं होगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी समुदाय अब आमने सामने आ चुके है और मराठा को तगड़े वोट बैंक और उनके चुनाव में खुलकर भाजपा के साथ

आ जाने से अब भाजपा मराठा वर्ग को नाराज नहीं करना चाह रही थी, वहीं इस बार विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स जिस तरह से भाजपा के समर्थन में आया है उसे भाजपा महाराष्ट्र की राजनीति में अपने लिए एक शुभ संकेत के तौर पर देख रही है। कयास लगाये जा रहे थे कि महाराष्ट्र में क्या भाजपा मध्यप्रदेश वाला फॉर्मूला लागू करने जा रही है। महाराष्ट विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन मे चुनाव लड़ने वाली भाजपा ने 132 सीटें जीतकर अपने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए है। महाराष्ट्र में भाजपा की प्रचंड जीत का सेहरा देवेंद्र फडणवीस के सिर बांधा जा रहा है और उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस भले ही मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हो लेकिन पार्टी आलाकामन ने अब तक उनके नाम को हरी झंडी नहीं दी थी। ऐसे में सवाल यहीं उठ रहा है कि क्या भाजपा आलाकमान देवेंद्र फडणवीस की जगह किसी नए चेहरे को राज्य की कमान सौंप सकता है, जैसा उसने मध्यप्रदेश में किया था। क्या महाराष्ट्र में भाजपा मध्यप्रदेश की तरह किसी ओबीसी चेहरे को आगे करेगी, यह भी बड़ा सवाल है। दरअसल पिछले साल हुए मध्यप्रदेश चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत का पूरा क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को दिया गया था, लेकिन पार्टी आलकमान ने डॉ. मोहन यादव को मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बना कर सभी को चौंका दिया था। अब क्या मध्यप्रदेश में सीएम चयन वाला फॉर्मूला अब भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र में लागू करने जा रहा है, यह देखना दिलचस्प होगा। वही मुख्यमंत्री पद को लेकर 'थ्री स्टेट फॉर्मूला' चर्चा का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तय करने के लिए बीजेपी तीन संभावित फॉर्मूलों पर विचार कर रही है :-

1. राजस्थान मॉडलः राजस्थान में चुनाव के बाद, बीजेपी ने पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी बीजेपी किसी नए और चौंकाने वाले चेहरे को सीएम पद सौंप सकती है। यह रणनीति गठबंधन में सभी दलों को संतुष्ट करने का प्रयास हो सकती है।

2. एमपी मॉडलः मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के बाद, पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर उनके कैबिनेट मंत्री मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना। महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे कैबिनेट के किसी वरिष्ठ नेता को सीएम बनाया जा सकता है।

3. बिहार मॉडलः 2020 के बिहार चुनाव में, तीसरे स्थान पर रही नीतीश कुमार की पार्टी (जेडीयू) को सीएम पद दिया गया था। इसी प्रकार, महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव से पहले किए गए वादे के आधार पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि यह चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। इसके साथ ही

सूत्रों के मुताबिक, एक अन्य संभावना यह है कि मुख्यमंत्री पद बीजेपी और शिवसेना के बीच ढाई-ढाई साल के लिए बांटा जाए। पहले ढाई साल बीजेपी का सीएम रहेगा, जबकि शेष अवधि के लिए शिवसेना (शिंदे गुट) का मुख्यमंत्री बनेगा। सनद् रहे कि बीजेपी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नए और युवा चेहरे को चुनने की योजना बना सकती है। इससे देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके साथ ही गठबंधन के संतुलन को बनाए रखने के लिए दो डिप्टी सीएम बनाने की योजना भी है। हालांकि बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट), और एनसीपी (अजित पवार गुट) के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए मंथन जारी है। अगले कुछ दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र का नेतृत्व कौन करेगा। महाराष्ट्र चुनाव 2024 में बीजेपी और सहयोगी दलों की प्रचंड जीत ने यह साबित किया है कि जनता ने महायुति पर भरोसा जताया है। अब सभी की नजरें मुख्यमंत्री के नाम और गठबंधन की भविष्य की रणनीति पर टिकी हैं। वही संभावना यह भी देखी जा रही है कि मुख्यमंत्री पद के लिए 2-2-1 फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। इस फॉर्मूले के मुताबिक, मुख्यमंत्री पद दो साल के लिए भारतीय जनता पार्टी, दो साल के लिए एकनाथ शिंदे गुट और एक साल के लिए अजित पवार के गुट को दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि अजित पवार गुट इस फॉर्मूले के लिए काफी उत्सुक है। हालांकि, मुख्यमंत्री का पद ढाई-ढाई साल या दो-दो-एक फॉर्मूले में नहीं बंटेगा क्योंकि फिलहाल महाराष्ट्र को स्थिर सरकार की जरूरत है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र करेंगे, यह बात कही जा रही थी।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में भारी बहुमत से जीतने के बाद भी महायुति के लिए राज्य में सरकार बनाना आसान नजर नहीं आ रहा था। एकनाथ शिंदे के समर्थक अभी भी अपने नेता को ही राज्य की कमान सौंपने पर अड़े हुए थे जबकि भाजपा हर हाल में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अब एकनाथ शिंदे के एक प्रस्ताव ने महायुति में शामिल दलों की सांसें तेज कर दी। राज्य के लोग यह जानना चाह रहे थे कि राज्य में सरकार का गठन कब होगा? बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने भाजपा के सामने प्रस्ताव रखते हुए कहा था कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनकी पार्टी सरकार को बाहर से समर्थन कर सकती है। शिवसेना ने दो टूक कह दिया है कि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रस्ताव से राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा नेताओं ने शिंदे के प्रस्ताव को नकारने में देर नहीं की। पार्टी चाहती है कि शिवसेना महायुति सरकार का हिस्सा बनी रहे। इधर शिंदे समर्थकों ने इस मामले में एनसीपी से भी समर्थन मांगा है। अजित पवार भी फडणवीस के नेतृत्व

में काम करने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं है। ऐसे में शिंदे और पवार का दबाव फडणवीस के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने के रास्ते को मुश्किल बना सकता है। बहरहाल शिंदे और फडणवीस के बीच जारी मुख्यमंत्री पद की जंग का फैसला ना तो राज्य में हो पा रहा था और ना ही केंद्र इस मामले का कोई समाधान निकाल पा रहा था। हर रोज यही कहा जा रहा था कि आज राज्य के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। बता दें कि इससे पहले एकनाथ शिंदे ने राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार के गठन तक उन्हें राज्य की कमान संभालने के लिए कहा है। वही महाराष्ट्र में शिंदे के बैकफुट पर आने के बाद अब इंतजार भाजपा के आलाकमान के फैसले का है। बता दें कि मुख्यमंत्री के चयन में जातिगत समीकरण की बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि सभी दलों के 288 विधायकों में से अधिकतर मराठा समुदाय से हैं। इस बीच मीडिया में खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने को तैयार हैं। शिवसेना को 10 से 12 मंत्रालय मिल सकते हैं। खबरों के मुताबिक शिंदे केंद्र में मंत्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी चाहते हैं। दूसरी तरफ शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि उन्हें अपने पिता एकनाथ शिंदे पर गर्व है, जिन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दरकिनार करते हुए ''गठबंधन धर्म'' का पालन करने का उदाहरण पेश किया है। सांसद ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि उनके पिता का महाराष्ट्र के लोगों के साथ अटूट रिश्ता है। श्रीकांत शिंदे ने कहा, ''मुझे अपने पिता और शिवसेना प्रमुख पर गर्व है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर भरोसा बनाए रखा और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को अलग रखते हुए गठबंधन धर्म का (बेहतरीन) उदाहरण पेश किया।'' शिवसेना के विधायक और प्रवक्ता संजय शिरशाट ने हालांकि कहा कि शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। शिरसाट ने कहा कि वे शायद उपमुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे। मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति के लिए ऐसा करना सही नहीं है।'' उन्होंने कहा कि शिवसेना किसी दूसरे नेता को उपमुख्यमंत्री बनाने के लिए कहेगी।

बहरहाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसे भी राज्य का अगला मुख्यमंत्री घोषित करेगा, वह उसका पूरी तरह समर्थन करेंगे। शिंदे ने कहा, मैंने कल प्रधानमंत्री मोदी (नरेंद्र मोदी) और अमित शाह को फोन किया था और उनसे (मुख्यमंत्री पद पर) फैसला करने को कहा था। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे जो भी निर्णय लेंगे, मैं उसका पालन करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी शिवसेना महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को नामित करने के भाजपा के फैसले का पूरा समर्थन करेगी। हमारी तरफ से कोई अडंगा नहीं है। शिंदे ने उन खबरों को भी खारिज कर दिया कि उनके नेतृत्व में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को शानदार जीत हासिल करने के बावजूद दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से वह निराश हैं। उन्होंने कहा कि कोई नाराज नहीं है। हमने महायुति के रूप में काम किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं मिलने से वह निराश हैं, शिंदे ने कहा कि, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको याद होगा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल का समर्थन किया था। यह पूछे जाने पर कि नए मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री कौन होगा। शिंदे ने कहा कि मैं इस प्रचंड जीत के लिए एक बार फिर महाराष्ट्र के लोगों और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में विधानसभा के दौरान व्यापक प्रचार किया। मैं अगले दिन प्रचार अभियान शुरू करने से पहले 2-3 घंटे ही सोता था। मैं हमेशा के लिए एक कार्यकर्ता हूं। मेरे लिए सीएम (चीफ मिनिस्टर) का मतलब कॉमन मैन (सीएम) होता है। शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर ढाई साल के कार्यकाल के दौरान समर्थन देने के लिए मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री बनने के छह महीने में ही महाराष्ट्र को तीसरे नंबर से नंबर 1 स्थान पर लाने के लिए काम किया। मीडिया में आई उन खबरों का हवाला देते, जिनमें कहा गया था कि वह चुनाव में महायुति की भारी जीत

के बावजूद पद छोड़ने के लिए कहे जाने से नाखुश हैं, शिंदे ने कहा, मैं निराश नहीं हूं। हम लड़ते हैं, रोते नहीं हैं। शिंदे ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर लोकप्रिय होने के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए काम किया। भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 सदस्यीय विधानसभा में 230 सीट जीतकर राज्य विधानसभा चुनावों में जोरदार वापसी की है। मीडिया खबरों के मुताबक शिंदे की तरफ से नई सरकार में गृह विभाग देने की मांग की गई थी। महायुति 1. 0 में यह विभाग डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखा था। इसके अलावा सीएम शिंदे ने कुछ और महत्वपूर्ण विभाग पार्टी को मिलने की मांग की है। फडणवीस के पास गृह के साथ कानून और न्याय के साथ जल संसाधन, कमांड एरिया डेवलपमेंट के अलावा एनर्जी और प्रोटोकॉल के विभाग थे। इतनी ही अन्य शर्तें राज्य में होने वाले महानगर पालिका चुनावों से जुड़ी हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार से उबरते हुए भाजपा ने 132 सीटों पर जीत दर्ज की जो महायुति के सभी घटक दलों में सर्वाधिक है। शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एकनाथ शिंदे पर मुख्यमंत्री पद पर दावा छोड़ने के लिए दबाव डाला। शिंदे के यह स्पष्ट करने के बाद कि मुख्यमंत्री पद के संबंध में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय उन्हें स्वीकार्य होगा, पटोले ने कहा कि महायुति गठबंधन को भारी जनादेश मिलने के बावजूद अगली सरकार बनाने में इतना समय लिया जा रहा है जिससे संदेह उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने शिंदे पर मुख्यमंत्री पद पर दावा छोड़ने का दबाव बनाया। महाराष्ट्र को इंतजार कराना (सरकार गठन के मामले में) निंदनीय है। कांग्रेस नेता ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखना होगा कि अगला मुख्यमंत्री कहीं वही तो नहीं, जिसके नाम की चर्चा है। पटोले ने कहा, अचानक नया चेहरा लाना भाजपा की परंपरा रहा है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने कहा कि शिंदे अप्रत्याशित जनादेश के कारण भ्रमित और हतप्रभ हैं।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर हाईवोल्टेज सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। राज्य में भले ही नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख 5 दिसंबर और समय शाम 5 बजे तय हो गया है लेकिन अब तक राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ ही था। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा ठोंक दिया। शिंदे ने दावा किया कि जनता उनको महाराष्ट्र के सीएम के रूप में वापस देखना चाहती है। वहीं एकनाथ शिंदे की समर्थक नेता लगातार कह रहे थे कि पूरा विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया था। वही महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की बंपर जीत के बाद नई सरकार के गठन में मुख्यमंत्री चेहरे के साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरे और विभागों के बंटवारे को लेकर भी मतभेद नजर आ रहा है। अगर मुख्यमंत्री का पद भाजपा के खाते में जाता है तो शिवसेना और एनसीपी अपने लिए बड़े और मलाईदार विभाग चाह रही है। वहीं भाजपा किसी भी हालात में बड़े और महत्वपूर्ण विभाग अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती है। इसलिए महाराष्ट्र में महायुति की बंपर जीत के पांच दिन बाद नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं हो सका है। वहीं अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते है तो वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की नई सरकार में क्या भूमिका होगी, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। अगर यह दो बड़े नेता डिप्टी सीएम बनते है तो इनके पास क्या विभाग होंगे, इस पर भी सबकी

नजरें होगी। वहीं मंत्रिमंडल में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के कितने-कितने मंत्री होंगे, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि शिंदे नई सरकार के गठन के फॉर्मूले से खुश नहीं हैं। ऐसे में नई सरकार के गठन को लेकर सबकी निगाहें एकनाथ शिंदे पर के रूख पर टिकी थी। वहीं इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को उपमुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, वहीं एकनाथ शिंदे केंद्र में मंत्री बन सकते है। बताते चले कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर पर्दा भाजपा विधायक दल की बैठक में होने की बात कही जा रही थी। पहले भाजपा विधायक दल की बैठक 1 दिसम्बर को होने की बात कही जा रही थी, लेकिन भाजपा सूत्रों के हवाले से 4 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की बैठक होने की खबरें आ रही है। यह तब है कि जब विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई है और उसके 132 विधायक चुने गए है। वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फिर कहा है कि वह नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी के फैसले का समर्थन करेंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे या उनकी जगह पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री होंगे। राज्य भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की ओर से यह दावा किया गया कि राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल कर दिया गया है और उन्हें पार्टी की बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। महाराष्ट्र में भाजपा की ओर से नए सीएम चेहरे के चयन में देरी का एक बड़ा कारण क्या जातीय समीकरण में पार्टी का उलझना है, यह सवाल भी अब खड़ा हो रहा था। ऐसे में प्रचंड जीत के बाद भी भाजपा के लिए मराठा चेहरे एकनाथ शिंदे को दरकिनार करना आसान नहीं हो रहा था। हालांकि शिंदे ने कहा कि वह राज्य में सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा शाह द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि 'लाडका भाऊ' (प्यारा भाई) का दर्जा मेरे लिए किसी भी अन्य चीज से ऊपर है। उन्होंने कहा कि हम सभी ने सरकार गठन पर चर्चा की। सहयोगी दलों के बीच अच्छा समन्वय है, हम सभी बहुत सकारात्मक हैं और हम लोगों द्वारा दिए गए स्पष्ट जनादेश का सम्मान करेंगे। हम जल्द सरकार बनाएंगे। शिवसेना नेता ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें भारी बहुमत से दोबारा चुना है और सर्वोच्च प्राथमिकता जनादेश का सम्मान करना है, न कि पदों के पीछे भागना। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे यह भली-भांति जानते हैं कि वे एक बार फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन उन्होंने यह कहकर राज्य की सियासत में सनसनी जरूर फैला दी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में एक आम आदमी की तरह काम किया है और इसलिए जनता चाहती है कि वे एक बार फिर मुख्यमंत्री बनें। शिंदे ने यह भी दोहराया कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन करेगी। उन्होंने नाराजगी की बात को भी खारिज किया है। साथ ही शिंदे ने कहा कि वे पूरी तरह भाजपा के साथ हैं। एक तरफ शिंदे मोदी और शाह के फैसले को मानने के लिए भी राजी हैं, दूसरी तरफ खुद का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए भी आगे बढ़ा रहे हैं। यह बात किसी के भी गले नहीं उतर रही है।

दरअसल, राजनीति के जानकार लोग शिंदे के इस दांव को उनके 'गेम प्लान' का हिस्सा मान रहे थे। मुख्यमंत्री शिंदे अपने डिप्टी सीएम रहे देवेन्द्र फडणवीस के नेतृत्व में कभी भी काम करना नहीं चाहेंगे। हालांकि शिवसेना के कुछ नेता चाहते हैं कि शिंदे को डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन, यदि शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लेते हैं तो राजनीतिक रूप से उनका कद कमजोर हो जाएगा। शिंदे के नए दांव के पीछे माना जा रहा है कि वे अपने सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने के साथ ही गृह मंत्रालय जैसा अहम पद चाहते हैं। यदि उनकी यह मांग मान ली जाती है तो वे एक तीर से दो शिकार करने में सक्षम होंगे। बेटे को डिप्टी सीएम बनाकर वे सरकार और पार्टी दोनों जगह अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल होंगे। यदि शिवसेना का दूसरा कोई नेता डिप्टी सीएम बनता है तो सरकार में उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी और पार्टी में एक नया नेतृत्व सामने आ जाएगा, जो कि न सिर्फ पार्टी बल्कि एकनाथ शिंदे के हित में भी नहीं होगा। यदि श्रीकांत शिंदे डिप्टी सीएम बनते हैं तो पॉवर घर में ही रहेगा और पार्टी पर उनकी पकड़ भी मजबूत रहेगी। हो सकता है कि श्रीकांत को डिप्टी सीएम का पद मिलने के बाद वे अपनी सीट बेटे के लिए छोड़ दें और खुद लोकसभा चुनाव लड़कर दिल्ली की ओर रुख कर सकते हैं। शिंदे की 'प्रेशर पॉलिटिक्स' की असल वजह भी यही बताई जा रही है। बहरहाल, सभी अटकले अब खत्म हो गई और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन गई। देवेंद्र फडनवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाये गये।

Jharkhand Assembly Election Result 2024

INDI alliance wins absolute majority

Propelled by a stellar show from its spear-head JMM, the ruling I.N.D.I.A bloc seemed on course to retain power in Jharkhand with a massive two-thirds majority, leaving the BJP-led NDA far behind in the vote count for the state's Assembly polls on Saturday. Of the total 81 seats in the state Assembly, I.N.D.I.A bloc has either won or is in the lead in 56 seats. In contrast, the main opposition Bharatiya Janata Party-led National Democratic Alliance has either won or continues to be ahead of rivals in only 24 constituencies.

The Jharkhand Loktantrik Krantikari Morcha, fighting its maiden election, has won the in Dumri seat. As per the Election Commission website at 7 p.m., the JMM has already bagged 23 seats, besides being ahead of rivals in 11 more, and could expect to pick up 34 seats if the trends hold. Considering the party contested 41 seats, it makes for a formidable strike rate of over 82 percent. JMM's alliance partners Congress (11 wins plus five leads) and Rashtriya Janata Dal (RJD - two wins and two leads) were in sight of 16 and four seats respectively, while the Communist Party of India (Marxist-Leninist) Liberation have triumphed in two seats. Among the NDA constituents, the BJP could end up with 21 seats, having already picked up 15 seats with leads in half a dozen more. The Janata Dal-United (JD-U) and Lok Janshakti Party(Ram Vilas) were in the lead in one constituency each. Chief Minister and top JMM leader Hemant Soren, who led the I.N.D.I.A campaign, completed a hatrick of wins from Barhait, having earlier coasted to victory from the seat in the 2014 and 2019 polls. Soren, who maintained a steady lead since the counting began at 8 a.m, won with a 39791 margin over his BJP opponent Gamliyel Hembrom.

The 49-year-old leader, who happens to be the eldest son of JMM founder Shibu Soren, has been helming the state since 2019, albeit with a five-month break earlier this year, when he was arrested for alleged corruption. There was further good news for the JMM and Hemant as the afternoon advanced as his wife Kalpana Soren and brother Basant seized the lead from Gandey and Dumka constituencies respectively after falling behind in the initial rounds. With the counting over, Kalpana was ahead of BJP's Muniya Devi by almost 17,000 votes.The result is yet to be officially announced.

According to the EC website, Basant Soren defeated BJP nominee Sunil Soren by 14588 votee. Among other prominent JMM nominees, Assembly Speaker Ravindra Nath Mahto was leading from Nala. After a day-long snake and ladder game, veteran politician Louis Marandi, who jumped ship to JMM after severing his long association with the BJP just before the poll, prevailed over the challenger from her former party Suresh Murmu by 5738 votes in Jama. On the NDA side, overcoming initial hiccups, former state Chief Minister Champai Soren, who contested as a BJP nominee from Seraikella, won by a 20477 margin over her JMM rival Ganesh Mahali. Champai, one of the founders of the JMM, had crossed over to the BJP after he was replaced as Chief Minister by Hemant Soren in July.

In Dhanwar, Jharkhand BJP unit president and former Chief Minister Babulal Marandi was leading by a 26,000 plus margin, with three-fourths of the polled votes already counted. However, another state BJP stalwart and Leader of the Opposition in Jharkhand Assembly Amar Kumar Bauri suffered a humiliating defeat in Chandankiyari. Bauri, who had been elected from the seat in 2019, finished third this time. Uma Kant Rajak of JMM, who had lost to Bauri five years back as a AJSU nominee, was elected, with Arjun Rajwar of Jharkhand Loktantrik Krantikari Morcha taking the second place. Other notable BJP candidates who lost were JMM chief Shibu Soren's daughter-in-law Sita Soren in Jamtara and Lobin Hembram in Borrio. Congress leader Irfan Ansari won with a 43,676 margin from Jamtara. In another piece of bad news for the NDA, AJSU-P chief and former Deputy Chief Minister Sudesh Mahto was trailing in Silli to his JMM rival.

UPPSC reschedules PCS (pre) exam to December 22, students call off protest

The Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) has rescheduled the PCS (Preliminary) Examination 2024 to December 22, which was earlier scheduled to be held on December 7 and 8. This reschedulement came following Chief Minister Yogi Adityanath's initiative to address students' concerns. Responding to the requests of students protesting in Prayagraj, the examination will now be conducted in a single day rather than over two days, as originally planned.

The revised exam will take place on December 22 in two shifts, from 9:30 am to 11:30 am and 2:30 pm to 4:30 pm. This change aims to ease travel and scheduling issues for candidates, enabling them to complete the exam in one day. Prompted by Chief Minister, UPPSC took swift action to amend the schedule and address students' demands efficiently. Meanwhile, satisfied with the decision of UPPSC to conduct the PCS (preliminary) exam in 'one day-one shift' as before and to form a committee on RO/ARO, the protest by the students ended on Friday for the time being. President of Chhatra Sangharsh Samiti Pankaj Pandey said, "The government has accepted 90 percent of our demands and it hoped that the committee formed will consider the remaining demands sympathetically. Therefore, we are going to end the protest. There are still some students at the protest site who are there voluntarily and they have nothing to do with the movement of Sangharsh Samiti."

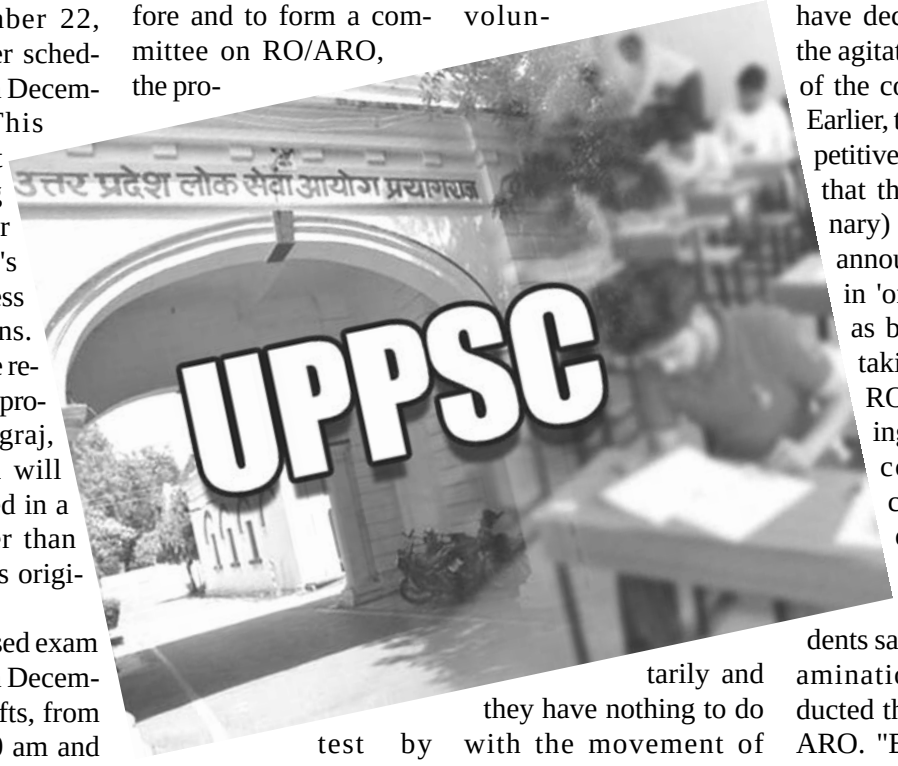

It may be noted that after the intervention of Yogi, the commission had decided to restore the old 'one day examination' system of PCS on Thursday. However, the agitation of the students for the restoration of the old system for Review Officer (RO) and Assistant Review Officer (ARO) continued till this morning. In the afternoon, the students have decided to suspend the agitation till the report of the committee comes. Earlier, the agitating competitive students had said that the PCS (Preliminary) examination was announced to be held in 'one day-one shift' as before but by not taking a decision on RO/ARO and talking about forming a committee, the commission has divided the student movement.

The students said that if PCS examination can be conducted then why not RO/ARO. "Even before this, these examinations have been conducted in 'one day-one shift'," they said. However, after the officials explained, the students decided to postpone their movement till the committee report came.

क्या सुनियोजित थी संभल की हिंसा?

● अमित कुमार

उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर 24 नवम्बर को हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई, लेकिन पुलिस का कहना है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो ऐसे में सवाल उठता है कि फिर कैसे पांच लोग मारे गए। बता दें कि हिंसा में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बता दें कि संभल हिंसा में मोहल्ला कोट तवेला निवासी नईम (35), फतेहऊनला सराय निवासी विलाल (22), इनके अलावा संभल के हयातनगर निवासी रोमान (40), तुर्तीपुर इला निवासी कैफ (19) और कोट गर्दी निवासी अयान (19) की भी मौत हुई है। बता दें कि संभल जिले में मस्जिद के सर्वे के दौरान भीड़ ने टीम के ऊपर जमकर पथराव कर दिया, जिसके बाद वहां हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। मामला शाही जामा मस्जिद का है। सरकार द्वारा मस्जिद के सर्वे करवाने के दौरान 24 नवम्बर की सुबह सर्वे टीम को घेर लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को भीड़ ने निशाना बनाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक इसमें 5 लोगों की मौत हुई है। करीब 25 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस दौरान भीड़ इकट्ठा हो गई और उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर पथराव करते हुए आगजनी भी कर दी, जिससे हंगामे की स्थिति बन गई। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लेते हुए कई थानों की फोर्स तैनात कर दी है। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएम सहित पुलिस के डीआईजी मुनिराज मौके पर पहुंचे। भीड़ द्वारा पथराव और आगजनी के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, फिलहाल क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि संभल शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किया गया था। जिसके चलते कोर्ट ने शाही मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे टीम ने पुलिस से मदद लेते हुए जामा मस्जिद की तरफ कूच करने वाले सभी तीनों रास्तों को बंद कर दिया। पुलिस-प्रशासन को पहले ही आभास था कि सर्वे का विरोध हो सकता है, जिसके चलते पीएसी और आरआरएफ को पहले ही तैनात किया गया था। पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी भी लगवाए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक संभल के उप जिलाधिकारी ने एसपी सांसद जिया उर रहमान वर्क के पिता ममलुकुर रहमान वर्क सहित 34 लोगों को पाबंद किया है। प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि अगर जैसे ही उसे सूचना मिलेगी कि कोई व्यक्ति शांति के लिए खतरा है या सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बन सकता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। संभल के एसपी ने कहा है कि बवालियों ने पुलिस-प्रशासन को टार्गेट करते हुए गाड़ियों में आगजनी की है। पुलिस उपद्रवियों को चिंहित करने का काम कर रही है और उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। भीड़ द्वारा किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है।

गौरतलब है कि यह हिंसा पूर्व सुनियोजित नहीं था बल्कि उकसाने पर हिंसा की गई है। पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारीमय फोर्स जामा मस्जिद पर लगे हुए थे। सर्वे के बाद जब टीम बाहर आने की तैयारी कर रहे थे तभी भीड़ मस्जिद के पीछे से आकर पुलिस पर पथराव करने लगी। पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ा, तभी उग्र लोगों ने वाहनों में आग लगा दी। मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने 5 लोगों की मौत की

पुष्टि की है, वहीं पुलिस-प्रशासन का दावा है कि उनके द्वारा गोली नहीं चलाई गई। आंसूगैस और रबड़ की गोलियां चलाई गई हैं। पुलिस ने अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक जक घर की छत से फायरिंग और पथराव पुलिस-प्रशासन पर किया गया। बवालियों को समझाने का प्रयास भी किया गया कि वे कानून को हाथ में न लें, किसी के बहकावे में आकर हिंसा को अंजाम देना घातक साबित होगा। मुरादाबाद कमिश्नर और एसपी का कहना है कि निश्चित रूप उकसावे के चलते पथराव और हिंसा की गई है। हालांकि सर्वे टीम के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल के साथ डीएम और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। कमिश्नर आंजनेय ने मीडिया को बताया कि कोर्ट के आदेश पर सर्वे का काम हो रहा है, 24 नवम्बर को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सर्वे का काम होना था, कुछ दिन पहले भी सर्वे हुआ जो पूरी तरह शांतिपूर्वक चला, कोई समस्या सामने नहीं आई। वादी और प्रतिवादी पक्ष दोनों सर्वे में मौजूद रहे, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत होती रही है, लेकिन आज अचानक से भीड़तंत्र ने सर्वे का विरोध करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। बताते चले कि उपद्रव के दौरान फायरिंग भी की गई। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। मुरादाबाद मंडल के आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कहा है कि उपद्रवी झुंड में आए थे। इनके तीन ग्रुप थे, जो कि लगातार फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग और पथराव के बीच पुलिस ने सर्वे करने आई टीम को सुरक्षित बाहर निकाला। बता दें कि इस घटना में एसडीएम सहित 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मस्जिद के आसपास के इलाके को सील कर दिया है। स्कूल कॉलेज और इंटरनेंट बंद कर दिया गया है। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि कई जगह ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने गोली चलाई है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने ऐसे किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे किसी की मौत हो जाए। एसपी ने कहा कि संभल थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उपद्रवियों की फायरिंग से कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। दीपा सराय इलाके में हिंसा ज्यादा हुई। यहां गोलीबारी की घटना की जांच की जा रही है। मंडल आयुक्त ने बताया कि एसडीएम रमेश चंद्र, क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार और एसपी के पीआरओ भी जख्मी हुए हैं। इस हिंसा में मारे गये एक युवक नईम की मौत हो गई थी। नईम के परिवार का आरोप है कि सीईओ की मौजूदगी में पुलिस की ओर से गोली चलाई जा रही थी। फायरिंग में गोली लगने से नईम की मौत हो गई। नईम प्रदर्शन में शामिल नहीं था। वह दुकान से रिफाइंड ऑयल लेने जा रहा था। दूसरी तरफ संभल की विवादित जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने मस्जिद परिसर के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए 25 नवम्बर को कहा कि मस्जिद की खुदाई की अफवाह फैलने से भीड़ उग्र हुई। जफर अली ने हिंसा के मामले में स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने अली के सभी आरोपों का खंडन किया है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने कहा कि जफर अली को पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है, वह खुद ही थाने में आए थे और अपनी बात रखकर चले गए। पहले पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिए जाने की खबर

संभल हिंसा

कब क्या हुआ

- 19 नवंबर की सुबह जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर कोर्ट में याचिका लगाई गई
- उसी दिन दोपहर 1 बजे सुनवाई हुई और शाम 4 बजे एडवोकेट कमिश्नर रमेश चंद राघव ने सर्वे का आदेश दिया
- शाम 5:30 बजे याचिकाकर्ता और एडवोकेट कमिश्नर DM राजेंद्र पेंसिया से मिले
- 6 बजे सर्वे टीम के साथ सभी मस्जिद पहुंचे और मुस्लिम पक्ष के साथ मीटिंग हुई
- करीब 7:30 बजे पहले दौर के सर्वे का काम पूरा हुआ
- 24 नवंबर को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के साथ अफसर दूसरे दौर के सर्वे के लिए मस्जिद पहुंचे

- इसी दौरान मस्जिद के बाहर भीड़ जुटी और लोगों ने पथराव कर दिया
- इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा पुलिसवाले घायल हो गए
- पुलिस ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क समेत 2700 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज की है

आई थी। इसके पहले जफर अली ने आरोप लगाया, मस्जिद का जो दोबारा सर्वे हुआ वह अदालत के आदेश से नहीं बल्कि सिर्फ जिलाधिकारी के आदेश पर हुआ था। यह सर्वे गैर-कानूनी तरीके से हुआ था। अली ने कहा, इस घटना के दोषी संभल की उपजिलाधिकारी वंदना मिश्रा और पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार हैं। इस सवाल पर कि इन अधिकारियों का क्या दोष है, अली ने कहा, उपजिलाधिकारी ने जिद करके वजू खाने का पानी निकलवाया, जबकि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कहा था कि डंडे से पानी की गहराई नाप ली जाए। मगर उपजिलाधिकारी की जिद पर जब हौज का पानी निकाला गया तो बाहर जमा लोगों में भ्रम पैदा हुआ कि मस्जिद में खुदाई की जा रही है। इसी से वे उग्र हो गए। उन्होंने आरोप लगाया, जब मस्जिद के बाहर भीड़ एकत्र हो रही थी तो पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार ने उन लोगों को गालियां दीं और लाठीचार्ज करवा दिया, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। अली ने आरोप लगाया, मैंने खुद पुलिस को भीड़ पर गोलियां चलाते देखा है। उन्होंने कहा, उपजिलाधिकारी वंदना

मिश्रा और पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार की वजह से ही झगड़ा हुआ और इन्हीं की वजह से मौतें हुई हैं। अली ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हैं कि वारदात में मारे गए बेगुनाह युवकों के परिजनों को उचित मुआवजा दें। पहले बताया गया था कि पत्रकार वार्ता के बाद पुलिस ने अली को हिरासत में ले लिया। लेकिन संभल के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जफर अली ने जो भ्रामक बयान दिया था, उसी संबंध में वह खुद थाने आए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया और न ही गिरफ्तार किया, वह अपनी बात रखकर थाने से चले गए। जिलाधिकारी ने जफर अली के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, मस्जिद के सर्वे का दूसरे दिन जो आदेश था वह एडवोकेट कमीशन का आदेश था। हम सिर्फ सुरक्षा-व्यवस्था के लिए वहां गए थे। उन्होंने कहा, दूसरे दिन सर्वे का आदेश हमने नहीं दिया था।

बताते चले कि शहर में हालात लगभग सामान्य हो चुके हैं लेकिन मस्जिद के पास के बाजारों में कारोबारियों का दावा है कि घटना के बाद से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान मस्जिद से आधा किलोमीटर दूर स्थित सर्राफा बाजार में स्थित सर्राफा दुकान मालिकों को हुआ है। सर्राफा व्यापारी अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि सर्राफा बाजार में 70-80 से ज्यादा दुकानें हैं। उन्होंने कहा कि शादी-ब्याह का सीजन होने के बावजूद हमारी बिक्री में काफी गिरावट आई है। उन्होंने दावा किया कि हिंसा के बाद सर्राफा बाजार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में सात मुकदमे दर्ज कर अब तक 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक मुकदमे में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और संभल सदर सीट से पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को नामजद किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हिंसा के मामले में फैजान, मोहम्मद अली और रेहान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 300 देसी बंदूकें, तीन खोखे और रबर की सात गोलियां भी बरामद कीं। पुलिस सूत्रों ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से

आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 30 टीमें बनाई गई हैं। कोट गर्वी इलाके से कथित दंगाइयों की 100 से ज्यादा तस्वीरें जारी की गई हैं।

गौरतलब है कि संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान उपजी हिंसा अब नया जामा पहनती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि यह दो नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें 4 बेगुनाह मौत की भेंट चढ़ गए। ये सभी पठान विधायक महमूद इकबाल अंसारी के समर्थक थे। सर्वे के दौरान भीड़ को उकसाने का आरोप संभल के नवनिर्वाचित तुर्क सांसद जिया उर रहमान बर्क के समर्थकों पर लगा है। सांसद समर्थकों की गोलीबारी से पठान, अंसारी और सैफी विधायक समर्थकों की मौत हुई है जिसके बाद क्षेत्र में देशी बनाम विदेशी का मुद्दा यानी तुर्क बनाम पठान का मुद्दा गरमा गया है। इस मुद्दे को योगी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने हवा देते हुए सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा है कि संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। तुर्क-पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की तत्परता सराहनीय है। भाजपा नेता अग्रवाल ने एक्स पोस्ट के माध्यम से इशारे में अपनी बात कहते हुए संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक इकबाल महमूद अंसारी को कटघरे में खड़ा किया है, वहीं सांसद और विधायक का नाम पुलिस की एफआईआर में भी दर्ज है। पुलिस की जांच में अब यह नया एंगल तुर्क और पठान वर्चस्व की लड़ाई भी आ गया है। पुलिस ने जामा मस्जिद सर्वे के दौरान टीम को घेरा और पथराव और गोलीबारी के बाद क्षेत्र में तनाव होने पर 30 थानों की पुलिस तैनात कर रखी है। वीडियो फुटेज जुटाकर जांच में जुटी हुई है। एक तरफ यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उसे इतिहास के साथ अपनी तरह से सेट किया जा रहा है, वहीं वहां काम कर रहे पत्रकार और स्थानीय लोग खारिज करते हुए इसे कपोल कल्पित बता रहे हैं। पहले वायरल हो रहा कथित इतिहास जान लीजिए।

पठान बनाम तुर्क के वर्चस्व की लड़ाई जानने के लिए उस इतिहास को जानना भी जरूरी है जिसका संदर्भ दिया जा रहा है। इतिहास के हवाले से कहा जा रहा है कि तुर्क और पठानों के बीच पहले भी संघर्ष रहा है, यह सही नहीं है। तुर्क मध्य एशिया से आए थे और स्लैब डायनेस्टी यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसके बाद खिलजियों ने एक पूरा राज्य स्थापित किया। दिल्ली सल्तनत को खिलजी के बाद तुगलक और तुगलक के बाद लोदी वंश ने संभाला था। लोदी अफगान के थे। उन्हें पठान नाम से जाना जाने लगा। वे अफगानिस्तान से आए थे जबकि बाकी लोग मध्य एशिया से आए थे। जिसके चलते आपस में संघर्ष या कोई मैचिंग प्वाइंट इनमें नहीं था। किसी भी स्तर पर एक ही नहीं थे और न ही कहीं पर मिले। संभल की बेल्ट रुहेलखंड से जुड़ी है। यहां जो समस्या चल रही है, उसमें कहीं भी तुर्क और पठान के बीच संघर्ष की कहानी नहीं है। यह दोनों भारत में एक ही टाइम में आकर राज्य की स्थापना करते तो इनमें संघर्ष होता। मोहम्मद गौरी के समय से स्टार्ट होकर स्लैब डायनेस्टी 1290 तक चली। वे लोग तुर्क थे। उसके बाद खिलजी वंश चला, उसके बाद तुगलक का स्टार्ट हुआ। इन लोगों ने बहुत लंबे पीरियड तक शासन किया। 1451 में लोदी वंश के लोगों, जो अफगानिस्तान के पठान हुआ करते थे, ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और दिल्ली सल्तनत को आगे चलाया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इनमें वर्चस्व के लिए संघर्ष नहीं हुआ। संभल में वर्चस्व के लिए तुर्क बनाम पठान का संघर्ष कहना न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि यहां ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हताहत दोनों तरफ के लोग हुए हैं। बेबुनियाद मुद्दे को हवा देकर माहौल खराब करने का प्रयास है। पत्रकारों ने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो बताया गया कि पुलिस ने गोली चलाई है। पुलिस की गोली से हमारे लोग मरे हैं जबकि पुलिस दावा कर

रही है कि उन्होंने गोली नहीं चलाई, रबर की गोलियां दागी थीं। पोस्टमार्टम में जामा मस्जिद सर्वे हिंसा के शिकार मृतकों के शरीर से कोई बुलेट की गोली नहीं मिली है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गोली सीने को चीरते हुए पीठ से पार हो गई होगी। मृतकों के शरीर से बुलेट रिकवर नहीं हुई है, इसलिए अब यह कहना भी मुश्किल है कि गोली किस विपन्न से चली है, कौन है संभल हिंसा में मारे गए युवकों का हत्यारा?

बहरहाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन की घोषणा की है। अपर मुख्य सचिव (गृह) दीपक कुमार की ओर से वार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने जनहित में और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा करेंगे। अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी अरविंद कुमार जैन शामिल हैं। आयोग चार प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें यह निर्धारित करना भी शामिल है कि क्या यह घटना किसी सुनियोजित आपराधिक साजिश का परिणाम थी। आयोग जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई कानून-व्यवस्था की तैयारियों की जांच करेगा, घटना की परिस्थितियों और कारणों का विश्लेषण करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों की सिफारिशें करेगा। संभल की एक अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद के पहली बार सर्वेक्षण किए जाने के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। अदालत ने यह आदेश उस याचिका पर दिया जिसमें दावा किया गया है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है, वहां पहले कभी हरिहर मंदिर था। मस्जिद का 24 नवंबर को दोबारा सर्वेक्षण किये जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी थी और इस दौरान प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गई तथा 25 अन्य जख्मी हो गए थे। आयोग को अधिसूचना जारी होने के दो माह के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है और समयसीमा को बढ़ाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। आयोग के निष्कर्ष सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। वही बताते चले कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेसीया ने यहां जारी एक बयान में कहा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि जनपद की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना 10 दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। यह कदम इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल हिंसा के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए संभल का दौरा करने वाला था। इस बीच, समाजवादी पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा कि संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए बनाए गए सपा प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं के घरों पर सरकार द्वारा पुलिस तैनात कर उन्हें संभल जाने से रोकने की घटना घोर निंदनीय एवं अलोकतांत्रिक है। भाजपा सरकार संभल हिंसा का सच छिपा रही है। सपा प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने की अनुमति मिले। सपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने कहा था कि विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय की नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर संभल जाएगा और वहां हुई हिंसा की विस्तृत जानकारी लेकर रिपोर्ट पार्टी प्रमुख को सौंपेगा। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि संभल मामले की जानकारी हासिल करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल 2 दिसंबर को वहां जाएगा। इस बीच, माता प्रसाद पांडेय ने लखनऊ में अपने आवास के बाहर संवाददाताओं से कहा कि गृह सचिव संजय प्रसाद ने मुझे फोन कर संभल नहीं जाने का अनुरोध किया था। संभल के जिला मजिस्ट्रेट ने भी मुझे फोन कर बताया कि जिले में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है इसलिए मैं अब पार्टी कार्यालय जाऊंगा और इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा। पांडेय ने कहा कि यह सरकार संभल में शायद अपनी गलतियों को छिपाने के लिए मुझे रोकना चाहती है क्योंकि हमारे दौरे से कई गलतियां सामने आ जाएंगी।

"Conversion only for reservation is fraud" Supreme Court slams Christian convert for claims of embracing Hinduism to avail SC quota

Religious conversion merely to avail quota benefits without "actual belief" in the other religion would amount to fraud on the Constitution, the Supreme Court has ruled. The apex court made this observation while upholding a Madras High Court order denying Scheduled Caste certificate to a Chrisitian convert woman who claims to be still embracing Hinduism while seeking the certificate for a Clerk job in Puducherry under scheduled caste category. A Bench of Justices Pankaj Mithal and R Mahadevan said that if the purpose of conversion/ reconversion is only to derive the benefit of reservation, the same cannot be allowed since it will defeat the objective of providing quota to the socially backward communities, as per a report by Bar and Bench.

The Supreme Court said that the State government's field verification clearly revealed that the marriage of appellant's parents was registered under the Indian Christian Marriage Act. Further, her baptism and court attendance were also documented and it showed that she was born as a Christian. There was nothing on record to show that she had reconverted to Hinduism, the Court noted. "In the present case, the appellant was a born Christian and could not be associated with any caste. In any case, upon conversion to Christianity, one loses her caste and cannot be identified by it. As the factum of reconversion is disputed, there must be more than a mere claim. The conversion had not happened by any ceremony or through Arya Samaj. No public declaration was effected. There is nothing on record to show that she or her family has reconverted to Hinduism and on the contrary, there is a factual finding that the appellant still professes Christianity," the Court noted.

अडानी समूह के खिलाफ आरोपों पर विपक्ष का हंगामा

राहुल गांधी का सवाल, अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए अडाणी?

अडाणी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा की बैठक आरंभ होने पर सदन ने दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि नियम 267 के तहत उन्हें कुल 13 नोटिस मिले हैं। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के जॉन ब्रिटास, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रमोद तिवारी और अखिलेश प्रसाद सिंह और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सहित कुछ अन्य सदस्यों ने अडाणी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर नोटिस दिए थे। खरगे ने कहा कि अडाणी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर है। उन्होंने कहा कि यदि सूचीबद्ध कामकाज को निलंबित कर दिया जाता है तो विपक्षी सदस्य बता सकते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पूरे देश को कैसे प्रभावित कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वैश्विक स्तर पर देश की छवि खराब हुई और फिर भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अडाणी का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि, इससे पहले खरगे कुछ और बोल पाते, सभापति ने कहा कि वह इस मुद्दे पर उनके नोटिस को अस्वीकार कर चुके हैं इसलिए वे इसे उठा नहीं सकते। इसके बाद कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और आसन से खरगे को बोलने देने की मांग करते रहे। सभापति ने सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन की अपील की। हालांकि जब हंगामा जारी रहा तो उन्होंने 11 बजकर 30 बजे सदन की कार्यवाही 11 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक दोबारा आरंभ होने पर सभापति ने सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। कुछ देर बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी दलों ने मांग की है कि गौतम अडाणी को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ जांच शुरू की जाए। विपक्ष ने अडाणी समूह के खिलाफ आरोपों पर चर्चा के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन की भी मांग की है। अडाणी समूह ने सभी

आरोपों को खारिज किया है।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडाणी की गिरफ्तारी की मांग फिर उठाई और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उन्हें बचा रही है। उन्होंने संसद परिसर में बातचीत में दावा किया कि अमेरिका में अडाणी को हजारों करोड़ रुपए की अनियमितता के मामले में अभ्यारोपित किया गया है, ऐसे में उन्हें जेल में होना चाहिए। इससे पहले अडाणी समूह की कंपनी अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहा कि अरबपति गौतम अडाणी और उनके भतीजे सागर अडाणी पर कथित रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिका के विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। कंपनी का यह भी कहना है कि उन पर प्रतिभूति धोखाधड़ी के तहत आरोप लगाया गया है जिसमें मौद्रिक दंड लगाया जाना शामिल है। इस बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि अडाणी अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्वीकार करेंगे? आप किस दुनिया में रह रहे हैं? निश्चित तौर पर वे इंकार करेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा है, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि छोटे-छोटे मामले में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार

किया जाता है। इन सज्जन को अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए के लिए अभ्यारोपित किया गया है। इनको जेल में होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अडाणी को बचा रही है। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले भी अडाणी की गिरफ्तारी की मांग की थी। बता दें कि न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा गौतम अडाणी और उनसे जुड़े अन्य लोगों पर गंभीर आरोप से भारत की राजनीति गरमा गई। कांग्रेस ने एक बार फिर अडाणी मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की। पार्टी नेता राहुल गांधी ने सवाल किया कि इतने घोटालों के बाद भी अडाणी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की गौतम अडाणी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सवाल किया कि वह जेल के बाहर क्यों हैं? उन्होंने कहा कि मोदी अडाणी के पीछे खड़े हैं और उन्हें बचा रहे हैं। अडाणी मोदी एक हैं तो सेफ हैं। अडाणी भाजपा को समर्थन देते हैं। राहुल ने कहा कि अडाणी घोटाले की जेपीसी जांच होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने सेबी प्रमुख माधवी बुच की भी जांच की मांग की। कांग्रेस ने एक्स पर अपने आधि कारिक अकाउंट पर पोस्ट कर कहा कि कि अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अडाणी ने 2,200 करोड़ रुपए की घूस दी। जब इस मामले की जांच होने लगी तो जांच रोकने की साजिश भी रची गई। अब अमेरिका में अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। अजीब बात है। कांग्रेस लगातार अडाणी और इससे जुड़े घपलों की जांच की बात कह रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी ताकत से अडानी को बचाने में लगे हैं। वजह साफ है- अडाणी की जांच होगी तो हर कड़ी नरेंद्र मोदी से जुड़ेगी। पार्टी नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि अब न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य लोगों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोप से अडानी की आपराधिक गतिविधियों के बारे में और अधिक चौंकाने वाले विवरण सामने आए हैं। इसमें कहा गया है कि उन्होंने 2020 और 2024 के बीच भारत सरकार के अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर (2,100 करोड़ रुपए) से अधिक की रिश्वत दी। रिश्वत का भुगतान भारत सरकार के सोलर पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए किया गया था, जिससे टैक्स के बाद +2 बिलियन (16,800 करोड़ रुपए) से अधिक मुनाफा होने का अनुमान था। इसमें आरोप लगाया गया है कि कई मौकों पर, गौतम अडानी ने रिश्वत की स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार के एक अधिकारी से मुलाकात की और इसका इलेक्ट्रॉनिक और सेलुलर फोन सबूत होने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि ये सब प्रधानमंत्री के स्पष्ट संरक्षण और कुछ नहीं होगा वाली सोच के साथ की गई धोखाधड़ी और अपराधों के एक लंबे रिकॉर्ड के अनुरूप है। तथ्य यह है कि अडानी की उचित जांच करने के लिए विदेशी अधिकार क्षेत्र का सहारा लिया गया है, इससे पता चलता है कि कैसे भारतीय संस्थानों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है और कैसे लालची और सत्ता के भूखे नेताओं ने दशकों के संस्थागत विकास को बर्बाद कर दिया है। रमेश ने कहा कि इस खुलासे के बाद SEBI की नाकामी भी एक बार फिर से सामने आती है, जो अडानी ग्रुप द्वारा प्रतिभूतियों और अन्य कानूनों के उल्लंघन की जांच कर रहा है और ग्रुप को उसके निवेश के स्रोत, शेल कंपनियों, आदि के लिए जिम्मेदार ठहराने में पूरी तरह से विफल रहा है। आगे का सही रास्ता यही है कि अडाणी महाघोटाले में प्रतिभूति कानून के उल्लंघनों की जांच को पूरा करने के लिए एक नए और विश्वसनीय SEBI प्रमुख को नियुक्त किया जाए और इसकी पूरी जांच के लिए तुरंत एक JPC का गठन किया जाए। आप सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि अडाणी समूह ने भारत को बदनाम किया है। यह बहुत गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को आगे आकर इसका जवाब देना चाहिए। अडाणी के खिलाफ सभी लंबित मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए और देश के अंदर और बाहर उनके द्वारा किए गए सभी भ्रष्टाचार देश के सामने आने चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद सत्र शुरू हो रहा है, हम एक बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आरोप साबित हो चुके हैं और दोषसिद्धि हुई है। बेहतर होता कि हमारी जांच एजेंसियां भी रिपोर्ट आने पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करतीं। उद्योगपतियों को नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए कहा जाना चाहिए, लेकिन एजेंसियां भी उनका बचाव कर रही थीं। SEBI अभी तक उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है कि गौतम अडानी ने अनुबंध पाने के लिए सरकारी अधिकारियों पर लाखों और करोड़ों रुपए खर्च किए। यह हमारे देश की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। एक उद्योगपति के कारण हमारी प्रतिष्ठा खोना दुर्भाग्यपूर्ण है।

बहरहाल, वही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अरबपति कारोबारी गौतम अडाणी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप में अमेरिका की अदालत में अभियोग चलाए जाने को लेकर भारतीय संसद में पैदा हुए व्यवधान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि यह कानून प्रवर्तन का मामला है। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अडाणी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग किए जाने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की। मिलर से सवाल किया गया था कि क्या आप अडाणी की गिरफ्तारी, उनके खिलाफ जांच और आरोपों का समर्थन करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं इस विषय पर विधि मंत्रालय के अपने सहकर्मियों से टिप्पणी करने का अनुरोध करूंगा। अमेरिकी प्राधिकारियों ने गौतम अडाणी और उनके भतीजे सागर अडाणी सहित सात अन्य लोगों पर 26.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। अडाणी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई थी।

केजरीवाल ने उठाए दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल

● संजय सिन्हा

दिल्ली में कानून व्यवस्था पर भाजपा और आम आदमी पार्टी में सियासी संग्राम छिड़ गया। आप ने जहां इस मुद्दे पर भाजपा और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा तो भाजपा ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। आप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि 'अब तो नींद से जागिए अमित शाह...'। दिल्ली में आम नागरिक छोड़िए खुद पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं! पार्टी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि धमाकों की आवाज से भी नहीं जाग रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली वाले अपनी सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार पर हमला तेज करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र दिल्ली में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने में नाकाम रहा है। पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मलेन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर जगह डर और असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने कहा कि महिलाएं शाम 7 बजे के बाद बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती हैं और मां-बाप अपनी बेटियों के बाहर जाने को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के होते हुए भी जबरन वसूली, गोलीबारी और अपराध की घटनाएं आम हो गई हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा और गृह मंत्रालय ने दिल्ली को जबरन वसूली और हिंसा का अड्डा बना दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली के क्षेत्र में 'आप' की उपलब्धियों को गिनवाया और कानून प्रवर्तन के कथित कुप्रबंधन के लिए भाजपा पर निशाना साधा। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, लेकिन यह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रही है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मौजूद थे। फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ-साथ, राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था को लेकर 'आप' और भाजपा आमने-सामने हैं। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने दिल्ली में NRC लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली से घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। आप को अराजक अपराध पार्टी बताते हुए भाजपा नेता ने कहा कि गैंगस्टर्स आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। गैंगस्टर और आप नेताओं में सांठगांठ का आरोप लगाते हुए पार्टी ने आप विधायक नरेश बाल्यान का एक ऑडियो भी जारी किया। कहा गया कि बाल्यान ने गैंगस्टर से बातचीत की। उत्तम नगर से आप विधायक पर धमकी देने और वसूली करने का भी आरोप लगाया गया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। इस विभाग का जिम्मा वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह संभाल रहे हैं।

104 बच्चों को तस्करी से बचाने वाली दिल्ली पुलिस की 2 महिला अधिकारी सम्मानित

● संजय सिन्हा

अपनी अद्वितीय प्रतिबद्धता और बहादुरी का परिचय देते हुए मात्र 9 महीने में 3 राज्यों से 104 बच्चों को तस्करी से बचाने वालीं दिल्ली पुलिस की हेड कॉन्स्टेबल सीमा देवी और सुमन हुड्डा को यहां एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। बेनेट विश्वविद्यालय और 'द टाइम्स ग्रुप' द्वारा आयोजित 'टाइम्स नाउ हीरोज' के पहले संस्करण में इन दोनों अधिकारियों को सम्मानित किया गया। बेनेट विश्वविद्यालय और 'द टाइम्स ग्रुप' द्वारा यहां जारी एक बयान में बताया गया कि साहस, प्रतिबद्धता और करुणा का परिचय देते हुए समाज के उत्थान में नि:स्वार्थ योगदान देने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित करने लिए आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन बेनेट विश्वविद्यालय के कुलपति और 'द टाइम्स ग्रुप' के प्रबंध निदेशक विनीत जैन ने किया। इसमें बताया गया कि इस कार्यक्रम में 'ऑपरेशन मिलाप' के प्रति अपनी अद्वितीय प्रतिबद्धता के जरिए बहादुरी की नई परिभाषा गढ़ने वाली दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल सीमा देवी और सुमन हुड्डा आकर्षण का मुख्य केंद्र रहीं। बयान में बताया गया कि इन अधिकारियों ने केवल 9 महीने में 3 राज्यों से 104 बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाकर उन्हें उनके परिवारों से मिलाया। इस मौके पर जैन ने कहा कि हमारा उद्देश्य 'टाइम्स नाउ हीरोज' के जरिए उन साधारण लोगों की असाधारण ताकत को सामने लाना है जो करुणा, साहस और उद्देश्य के साथ समाज का नेतृत्व करते हैं। इस पहल का मकसद असल जीवन के उन नायकों के बारे में बताना है जो लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, जो साहस और निस्वार्थ भाव से कार्य करके लोगों के जीवन को बदलते हैं और हमारे समाज के ताने-बाने को मजबूत करते हैं। सीमा देवी ने 'टाइम्स हीरोज अवॉर्ड' प्राप्त करने के बाद कहा कि यह सब करने से मुझे संतुष्टि मिलती है। मुझे

एक अभिभावक के रूप में अपने स्वयं के अनुभवों से प्रेरणा मिलती है। हम ड्यूटी पर सिर्फ वर्दी ही नहीं पहनते। जब हमें कोई बच्चा मिलता है तो हम बिल्कुल एक मां या बहन की तरह उसे समझने और उससे एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने 13 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों को निशाना बनाकर किए जाने वाले सोशल मीडिया अपराधों में खतरनाक वृद्धि पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी को रोकने के लिए पहला कदम यह है कि भीख मांगने वाले बच्चों को पैसे देना बंद कर दिया जाए। अगर आप पैसे देना बंद कर देंगे तो आपको सड़कों पर कम बच्चे दिखेंगे। प्रयास करें। सुमन हुड्डा ने कहा कि बच्चों को उनके परिवारों से फिर से मिलाने पर मुझे बहुत गर्व और राहत महसूस होती है। हम बच्चों और उनके परिवारों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। बच्चे अपने माता-पिता से कुछ भी बात करने से कतराते हैं क्योंकि वे उनसे नाराज होते हैं लेकिन वे हमें मार्गदर्शक मानकर हमें सुनते हैं।

स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन

● अमित कुमार

संगीत की देवी और बिहार की स्वर कोकिला के रूप में अपनी पहचान बनाने वालीं पद्मश्री से सम्मानित शारदा सिन्हा का निधन 5 नवम्बर की रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में हो गया। एम्स के एक अधिकारी ने बताया कि शारदा सिन्हा का सेप्टीसीमिया के कारण 'रिफ्रैक्टरी शॉक' के चलते रात 9 बजकर 20 मिनट पर निधन हो गया। शारदा सिन्हा को मल्टीपल मायलोमा (एक प्रकार का ब्लड कैंसर) था और स्वास्थ्य जटिलता उत्पन्न होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। छठ गीतों को घर-घर तक पहुंचाने वाली 72 वर्षीय शारदा सिन्हा छठ महापर्व के पहले दिन नहाय-खाय पर ही छठी मंईयां की गोद में निर्वाण को प्राप्त हुईं। वे 11 दिनों से एम्स में भर्ती थीं। बीते दिनों उनकी तबीयत बिगड़ने पर 26 अक्टूबर को एम्स में भर्ती कराया गया था। 5 नवम्बर की देर रात उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर मां शारदा सिन्हा के निधन की जानकारी दी। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर फ्लाइट से पटना लाया गया। एयरपोर्ट पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, जदयू के नेता और मंत्री महेश्वर हजारी समेत कई नेताओं और कलाकारों ने स्वर्गीय शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। पटना के जिलाधिकारी भी मौजूद थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर के साथ उनके परिजन और पुत्र अंशुमन भी पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट से स्वर्गीय शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर उनके आवास राजेंद्र नगर ले जाया गया। जहां लोगों के दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया। वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि बिहार कोकिला, पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने शारदा

सिन्हा जी के निधन की सूचना मिलते ही स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली को स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के परिवार के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर उनका पार्थिव शरीर वायुयान (फ्लाइट) से पटना भेजने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी पटना को निर्देश दिया है कि राजकीय सम्मान के साथ स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के अंतिम संस्कार हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था ससमय सुनिश्चित करेंगे। बताते चले कि इसी वर्ष 22 सितंबर को शारदा सिन्हा के पति ब्रजकिशोर सिन्हा का 80 वर्ष की उम्र में ब्रेन हेम्ब्रेज के कारण निधन हो गया था। पति के निधन के बाद शारदा सिन्हा धीरे-धीरे कमजोर होते चली गईं थीं। तबीयत बिगड़ने के बाद शारदा सिन्हा को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अक्टूबर में जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो उनकी खाने-पीने की आदतों में भी समस्या आने लगी थी। उनके निधन से कला जगत में शोक की लहर है। बता दें कि महापर्व छठ के आरंभ होने से चार दिन पूर्व उन्होंने छठ गीत 'दुखवा मिटाई छठी मैया, रऊए आसरा हमार' जारी किया था। एम्स अस्पताल से ही उनके बेटे ने गीत को इंटरनेट मीडिया पर जारी कर लोगों को छठ की शुभकामना दी थी।

अपने छठ गीतों के लिए मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शारदा सिन्हा भारत की मशहूर लोक गायिका थीं, जो खासकर बिहार, झारखंड, और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों के लिए जानी जाती थीं। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के समस्तीपुर में एक संगीतमय परिवार में हुआ था। शारदा ने बचपन से ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की और अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से की। उनकी आवाज को भारत के पारंपरिक लोक संगीत का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने छठ गीतों के साथ-साथ मैथिली, भोजपुरी और मगही में भी कई लोकप्रिय गाने गाई हैं। उन्हें अक्सर इस क्षेत्र के लिए एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में जाना जाता था। वो छठ पूजा के दौरान नियमित रूप से प्रस्तुति देती थीं। मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के बिहार दौरे के समय भी उन्होंने मंच की शोभा बढ़ाई थी। वर्ष 1988 में, उन्होंने मॉरीशस के 20वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने गायन की प्रस्तुति दी थी। वर्ष 2009 के बिहार विधानसभा चुनाव में शारदा सिन्हा चुनाव आयोग की ब्रांड एंबेसडर भी थीं। अपने गीतों से सबको मंत्रमुग्ध करने वाली गायिका शारदा सिन्हा संगीत के साथ-साथ पढ़ाई में भी अव्वल थीं। उन्होंने संगीत में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। बिहार की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर हुई शारदा सिन्हा का जन्म सुपौल जिले के हुलास में हुआ था। उनके पिता खुद शिक्षा विभाग में सीनियर ऑफिसर थे। घर में उनके पढ़ाई- लिखाई का अच्छा माहौल था। गायिका ने भी बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री ली थी। इसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। शारदा सिन्हा ने मगध महिला कॉलेज, प्रयाग संगीत समिति और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। लोकगायिका शारदा सिन्हा समस्तीपुर के महिला महाविद्यालय में संगीत विभाग की प्रोफेसर रहीं थीं। इसके बाद संगीत वे यहीं इसी विभाग की एचओडी भी बनीं। गायिका ने कई स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया था। वही शारदा सिन्हा के पति का नाम बृजकिशोर सिन्हा था। वह शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय डिप्टी डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। इसी साल उनके पति का भी निधन हो गया था और तभी से वह भी सदमे में थीं। उनके दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी।

गौरतलब है कि शारदा सिन्हा के परिवार के साथ उनके करियर में ससुराल वालों में भी अहम योगदान निभाया। वैसे तो शारदा के परिवार में 30-35 सालों तक किसी बेटी का जन्म नहीं हुआ था। उनका जन्म काफी मन्नतों के बाद हुआ। उनके हुनर की पहचान उनके पिता ने की और फिर बेटी को संगीत सिखाने का फैसला लिया। अपने पीहर से संगीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर ब्याह के बाद भी ये जारी रहा। उन्हें पति का सपोर्ट मिला तो ससुर ने भी खूब साथ दिया। मगर शुरुआत में सास, बहू के गाने-बजाने से नाराज रहती थीं क्योंकि इनसे पहले परिवार की कोई बहु घर से बाहर काम के लिए नहीं गई थी। लेकिन बाद में सास ने ही छठ आदि लोक रिवाजों की पूरी जानकारी सिखाईं और समझाई भी। सनद् रहे कि शारदा सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक में की थी और धीरे-धीरे

वह बिहार और उत्तर भारत में लोकप्रिय होती चली गई। उनके गाए हुए छठ गीत जैसे "हो दीनानाथ", "केलवा के पात पर", और "पाहन-पानि" बिहार के छठ पर्व में अनिवार्य से हो गए हैं। उन्होंने छठ पूजा के लिए कई ऐसे गीत गाई हैं जो हर साल लाखों लोग सुनते और गाते हैं। उनकी आवाज में एक गहराई और सादगी है जो सीधे लोगों के दिलों को छू लेती है। टी-सीरीज, एचएमवी और टिप्स की ओर से जारी नौ एल्बम में वे 62 छठ गीत गा चुकी हैं। साल 1978 में छठ पर्व पर आया 'उग हो सुरुज देव' गीत आज भी घाटों पर सुना जाता है। लोग गायिका के गाए हुए ज्यादातर गीतों को सुनकर ही लोग छठ का त्योहार बड़ी ध ूमधाम से मनाते हैं। शारदा सिन्हा के कुछ लोकप्रिय गीतों में 'छठी मैया आई ना दुआरिया', 'कार्तिक मास इजोरिया', 'द्वार छेकाई', 'पटना से' और 'कोयल बिन' हैं। वैसे तो शारदा सिन्हा ने कई भोजपुरी फिल्मों और एल्बम में गाने गाए थे, लेकिन उनका अपना पसंदीदा भोजपुरी गाना था, भोजपुरी फिल्म 'गंगा मइया तोहे पियरी चढइबो' का 'लाली लाली होठवां से बरसे ललइया हो कि रस चुएला, जैसे अमवा के मोजरा से रस चुएला था'। इसके अलावा सिन्हा ने बॉलीवुड फिल्मों में भी गाना गया था। इनमें 'गैंग्स ऑफ वासेपुर- टू' के 'तार बिजली', 'हम आपके हैं कौन' के 'बाबुल' और 'मैंने प्यार किया' के 'कहे तो से सजना' जैसे गाने शामिल हैं। 'बिहार कोकिला' के नाम से मशहूर एवं सुपौल में जन्मीं सिन्हा छठ पूजा एवं विवाह जैसे अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीतों के कारण अपने गृह राज्य बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मशहूर थीं। बताते चले कि शारदा सिन्हा का संगीत पारंपरिक और आधुनिकता का संगम है। वे अपने गीतों में संगीत का नया प्रयोग करते हुए भी उनकी प्राचीनता को बनाए रखती थीं। उनकी आवाज में एक मिठास और गहराई है जो सुनने वालों को अपनी ओर खींचती

भोजपुरी गीत

है। लोकगीतों के माध्यम से उन्होंने ना केवल बिहार की संस्कृति को उजागर किया बल्कि उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई। उनका संगीत ग्रामीण भारत की आवाज को प्रतिध्वनित करता है। उन्होंने ग्रामीण समाज के संघर्षों, खुशियों और परंपराओं को अपने गीतों में पिरोया था, जिससे लोगों को अपने जड़ों से जुडने का मौका मिलता है। शारदा सिन्हा ने कई मंचों पर इस बात को कहा है कि भोजपुरी में जो नई पीढ़ी के गायक आ रहे हैं, उन सभी में बेहतरीन क्षमता है। उन सभी को अपनी इस क्षमता को रचनात्मक दिशा में लगाने की जरूरत है। अगर वह बढ़िया और साफ सुथरा गाना गाएंगे तो उनकी बेहतर पहचान बन सकती है।

बताते चले कि शारदा सिन्हा साल 1974 में पहली बार गाना शुरू किया था। उन्हें 1991 में पद्मश्री अवॉर्ड मिल चुका है। साल 2000 में शारदा सिन्हा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2006 में बिहार कोकिला को राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2015 में बिहार सरकार ने उन्हें बिहार सरकार पुरस्कार से नवाजा। साल 2018 में भारत सरकार ने शारदा सिन्हा को पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके साथ ही बिहार कोकिला के अलावा भोजपुरी कोकिला, भिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार रत्न, मैथिली विभूति सहित कई सम्मान मिले। बता दें कि शारदा सिन्हा की बिगड़ते तबीयत को देखते हुए पीएम मोदी ने अंशुमन सिन्हा से कहा था कि वे बिल्कुल मजबूती से अपनी मां का इलाज कराएं।

बहरहाल,स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित प्रदेश के विभिन्न नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार कोकिला, पद्म श्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा का निधन दु:खद है। वे मशहूर लोक गायिका थीं। उन्होंने कहा कि शारदा सिन्हा के छठ महापर्व पर सुरीली आवाज में गाए मधुर गाने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी भागों में गूंजा करते हैं। उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को दु:ख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है। इधर, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि शारदा सिन्हा का निधन न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की संगीत और लोक संस्कृति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनकी मधुर आवाज और लोकगीतों ने हमारे लोक संगीत को एक नई पहचान दिलाई। बिहार की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने में उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा, शारदा जी ने अपने संगीत से हमें और हमारी संस्कृति को जो गौरव प्रदान किया, वह सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेगा। उनके निधन से संगीत जगत में जो शून्यता उत्पन्न

हुई है, उसे भर पाना असंभव है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और उनके प्रशंसकों के साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्वर कोकिला निधन पर कहा कि बिहार की सांस्कृतिक नायिका तथा बिहार की स्वर कोकिला बहन शारदा सिन्हा का जाना बिहार की लोक संस्कृति एवं विरासत के लिए अपूरणीय क्षति है। छठ का महापर्व बिना उनके गाए गीतों के अधूरा लगता है। पूरा बिहार शोक की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शारदा सिन्हा के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि शारदा सिन्हा का जाना, बिहार के लोक संगीत और संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपनी अद्वितीय आवाज से बिहार की लोक परंपराओं को संजोए रखा और उसे देश-विदेश में ख्याति दिलाई। दिलीप जायसवाल ने अपने शोक संदेश में कहा, शारदा सिन्हा ने लोकगीतों के माध्यम से हमारे समाज की भावनाओं को अभिव्यक्त किया और लोक धरोहर को नई पहचान दी। उनकी मधुर आवाज ने बिहार के लोक संगीत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से अपने शोक संदेश में कहा कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी के निध न से स्तब्ध हूं। उनकी गायन ने बिहार की संस्कृति, भोजपुरी संगीत और छठ महापर्व की महानता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक गरिमामयी पहचान दिलाई। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि स्वर कोकिला, पद्मश्री शारदा सिन्हा के निधन से पूरा बिहार मर्माहत है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा संयोग है जिन्होंने छठी मइया के गीत को देश दुनिया में पहुंचाया, आज नहाय खाय के दिन हमारे बीच नहीं रहीं। शारदा सिन्हा के निधन पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि शारदा सिन्हा के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध और मर्माहत हूं। पूरे बिहार के लोग शारदा सिन्हा के निधन की खबर से मर्माहत हैं। पूरे देश में जिस तरीके से लोक गायिकी के क्षेत्र में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी, उसे ना कोई भूल सकता ना कोई मिटा सकता है। शारदा सिन्हा ने लोक गायिका के क्षेत्र में एक लंबी लकीर खींची। उनका निधन बिहार के लिए विशेष तौर पर अपूरणीय क्षति है। इसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है।

सनद् रहे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनका सुमधुर गायन अमर रहेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने 'एक्स' पर लिखा, "बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। बिहारी लोक गीतों को मैथिली और भोजपुरी में अपनी मधुर आवाज देकर शारदा सिन्हा जी ने संगीत जगत में अपार लोकप्रियता पायी।" उन्होंने लिखा, "आज छठ पूजा के दिन उनके मधुर गीत देश-विदेश में भक्ति का अलौकिक वातावरण बना रहे होंगे। उन्हें वर्ष 2018 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उनका सुमधुर गायन अमर रहेगा। मैं उनके परिवारजन एवं प्रशंसकों के प्रति गहन शोक-संवेदना व्यक्त करती हूं।" प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। उन्होंने कहा, आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति!

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने लोकप्रिय लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर शोक व्यक्त किया। गंगवार ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर अत्यंत दु:खद है। उनके निधन से भारतीय लोक संगीत ने एक अनमोल रत्न खो दिया है। भारतीय संगीत और लोक गायन में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। इस कठिन समय में उनके परिवार और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।'' हेमंत सोरेन ने 'एक्स' पर लिखा, ''अपनी आवाज से छठ एवं अन्य त्योहारों को जीवंत करने वाली स्वर कोकिला आदरणीय शारदा सिन्हा जी के निधन की दु:खद खबर मिली। स्व. शारदा जी नारी सशक्तिकरण की विराट मिसाल थीं। उनका चले जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई शायद ही कभी पूरी हो पाएगी। छठी मइयां स्व. शारदा जी की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दु:ख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे।'' यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक गायिका, पद्म भूषण शारदा सिन्हा के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर उनके निधन को संगीत जगत की अपूरणीय क्षति बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि प्रख्यात लोक गायिका, पद्म भूषण डॉ. शारदा सिन्हा जी का निधन अत्यंत दु:खद व संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने उत्कृष्ट पारंपरिक गायन के माध्यम से मैथिली, भोजपुरी सहित अनेक लोक भाषाओं और लोक संस्कृति की सेवा की तथा राष्ट्रीय पटल पर उन्हें सम्मान दिलाया। सीएम योगी ने लिखा-प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा उनके शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों को यह अथाह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। शांति!

गौरतलब है कि जीवन और संगीत में शारदा सिन्हा की यात्रा, जुनून और दृढ़ संकल्प से चिह्नित है, जिसके कारण उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 15 करोड़ रुपये है। यह वित्तीय सफलता उनके समर्पण, रचनात्मकता और सीमाओं को पार करने की क्षमता का प्रमाण है। जबकि उनके गायन और अभिनय ने उनकी विरासत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी उपस्थिति ने उनके व्यक्तित्व में एक नया आयाम जोड़ा है।

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
7004408851
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

★ कब एक पति द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ उसके मर्जी से शारीरिक संबंध बनाने पर बलात्कार की कोटि में आता है ?

यदि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम है तो पति द्वारा किया गया मैथुन बलात्कार की श्रेणी में आता है साथी यदि जो कि अपनी पत्नी के साथ जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रकार या रीति रिवाजों के अधीन उससे अलग रह रही हो तो उसकी सहमति के बिना मैथुन करता है तो वैसे पति को 2 वर्षों से लेकर 7 वर्षों तक का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है इस अपराध के लिए दंड की व्यवस्था भारतीय दंड संहिता की अधिनियम की धारा 376 ख में किया गया है यह एक संगीन एवं अजमानती अपराध होता है इसकी ट्रायल सेशन न्यायालय में किया जाता है।

★ क्या दो नपुंसको या दो पुरुषों या स्त्रियों के बीच किया गया विवाह वैध होता है?

दो नपुंसको के बीच किया गया विवाह शुन्य होता है यही बात दो पुरुषों के बीच या दो महिलाओं के बीच किया गया विवाह के ऊपर भी लागू होता है क्योंकि विवाह के लिए दो पक्ष कार होनी चाहिए जिनमें एक पक्षकार का पुरुष होना तथा दूसरे पक्षकार का स्त्री होना आवश्यक होता है इसलिए यदि दो पुरुष आपस में विवाह करते हैं तो वह विवाह शुन्य माना जाएगा या दो महिला आपस में विवाह करती है तो भी वह विवाह शुन्य होता है।

★ दहेज हत्या के एक मामले में सेशन जज ने दहेज हत्या 304इ एवं हत्या 302 भारतीय दंड संहिता की धाराओं में आरोप गठन किया है क्या यह सही है ?

सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने 22 नवंबर 2010 को दहेज हत्या संबंधी राजवीर एवं अन्य बनाम राज्य 2010 के एक मामले का निस्तारण करते हुए देश की सभी निचली अदालतों को यह निर्देश दिया है कि दहेज प्रताड़ना से हुई मौत के मामलों में वह मुदालय पर धारा 304 बी के साथ 302 हत्या के अपराध का भी आरोप गठन करें ताकि इस जघन्य अपराध के लिए उसे मौत की भी सजा दी जा सके यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने हरियाणा के दहेज हत्या के उक्त मामले में सुनवाई के दौरान दिया था।

★ क्या फुटपाथ पर अपना जीवन गुजर बसर करने वाले गरीबों के आवास के लिए कोई कानून बनाया गया है?

फुटपाथ पर अपना जीवन बिताने वाले लोगों को आश्रय उपलब्ध कराना यह सरकार की जिम्मेवारी है इसके लिए इंदिरा आवास योजना रैन बसेरा इत्यादि कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2001 की रिट याचिका संख्या 196/ 2001 पर दिए निर्णय में न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को आश्रय देने की जिम्मेदारी सरकार की है न्यायालय के कमिश्नर डॉ एन सी सक्सेना और स्पेशल कमिश्नर हर्ष मंडल ने यह निर्णय 2 फरवरी 2010 को दिया था।

★ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर कितने वर्षों तक की सजा हो सकती है?

जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति पर जो लोक सेवक हो उस समय जब वैसे लोक सेवक होने के नाते वह अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो तो इस आशय से की उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने या डराने या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधि पूर्वक निर्वहन में की गई या की जाने के लिए किसी बात के परिणाम स्वरुप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास की अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जा सकता है इसकी व्यवस्था भारतीय दंड संहिता की धारा 353 में की गई है।

★ क्या न्यायालय के खिलाफ पत्रिका या किसी भी मीडिया में समाचार छापना या दिखाना न्यायिक अवमानना का अपराध होता है?

न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 (कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट 1971) की धारा 5 के अनुसार न्यायिक कार्य की उचित आलोचना अवमानना नहीं कहलाती है ।इस धारा के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे मामले की जिसकी सुनवाई हो चुकी हो और उसमें न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से फैसला दिया जा चुका हो उसके गुण अवगुण पर किसी उचित आलोचना का प्रकाशन करने या प्रसारण करने पर न्यायालय अवमानना का अपराध नहीं होता है कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के अपराध मे धारा 12 के अनुसार जो कोई व्यक्ति न्यायालय अवमानना का दोषी पाया जाएगा उसे सादे कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकती है दंडित किया जा सकता है।

★ क्या दो नपुंसको या दो पुरुषों या स्त्रियों के बीच किया गया विवाह वैध होता है?

दो नपुंसको के बीच किया गया विवाह शुन्य होता है यही बात दो पुरुषों के बीच या दो महिलाओं के बीच किया गया विवाह के ऊपर भी लागू होता है क्योंकि विवाह के लिए दो पक्ष कार होनी चाहिए जिनमें एक पक्षकार का पुरुष होना तथा दूसरे पक्षकार का स्त्री होना आवश्यक होता है इसलिए यदि दो पुरुष आपस में विवाह करते हैं तो वह विवाह शुन्य माना जाएगा या दो महिला आपस में विवाह करती है तो भी वह विवाह शुन्य होता है।

★ न्यायालय में झूठी गवाही देने पर कितने वर्षों तक की सजा हो सकती है?

अगर कोई गवाह जानबूझकर किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी चरण में झूठा साक्ष्य देता है या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी चरण में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष गढ़ता है तो वैसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अनुसार 7 वर्षों तक की सजा हो सकती है साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है यह एक असंगेय एवं जमानती अपराध होता है जिसका विचारण फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है।

आवश्यकता

अगर आप में है आत्मविश्वास और तीव्र इच्छा, तो मौका है इसे पूरा करने का....

बिहार की सबसे लोकप्रिय पत्रिका

केवल सच

और

केवल सच TIMES

को बिहार के हर जिले, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि (डोर टू डोर मार्केटिंग) एवं प्रसार के कार्य के लिए परिश्रमी एवं जुझारू युवक/युवतियों की आवश्यकता है।

योग्यता:-

जिला ब्यूरो	प्रखंड संवाददाता	पंचायत संवाददाता	विज्ञापन प्रतिनिधी
स्नातक उतीर्ण	स्नातक/इंटर	स्नातक/इंटर/मैट्रिक	स्नातक/इंटर/मैट्रिक

संपर्क करे:-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, कंकड़बाग

पटना-20, मो.- 9431073769, 9955077308

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008